● वर्ष-3
● अंक-50
रायपुर, शुक्रवार
06 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› साल भर में एक बार खिलता...

भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है भू-पे से सीखें : अनुराग ठाकुर

भू-पे एप्प किया लॉन्च, स्कैन करते ही भूपेश सरकार के सारे भ्रष्टाचार होंगे सामने, केंद्रीय मंत्री के साथ डॉ. रमन सिंह ने की पत्रकार वार्ता

रायपुर। केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के काले कारनामों को दर्शाने वाले भूपे-एप को लांच करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो के जरिये कांग्रेस सरकार ने छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि जब से भूपेश सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके ईजाद कर रही है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहली बार ऐसी सरकार आई है जो नए-नए तरीके निकाल कर भ्रष्टाचार के नए-नए आयाम तैयार करती है। दो नंबर की शराब कैसे बेची जाती है, कोयला परिवहन में कैसे खाया जाता है, हर मामले में भ्रष्टाचार के नए प्रयोग यहां हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा यहां के मुख्यमंत्री से सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रमुख वादे किए थे, वह पूरे क्यों नहीं हुए। वादे पूरे करना तो दूर, बदले में माफिया राज स्थापित कर दिया। छत्तीसगढ़ में लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, माफिया पर माफिया और माफिया राज से छत्तीसगढ़ माफी चाहता है। मैंने यहां के युवाओं में जो आक्रोश देखा है, वह गवाही दे रहा है कि युवा अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। युवा प्रतीक्षा कर रहे थे कि इनका भी समय आएगा। इनको रोजगार का अवसर मिलेगा जो ढाई हजार रुपए प्रति महीना

बेरोजगारी भत्ता देने कहा था,नहीं दिया। युवा उसकी ब्याज सहित वसूली करेगा। अब तक कांग्रेस के नेताओं के जरिए वसूली हो रही थी। अब महिलाएं अपने साथ हुई वादाखिलाफी के लिए ब्याज सहित बदला लेंगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि अगर किसानों की उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कोई करता है तो केंद्र सरकार करती है। खरीदी भी केंद्र सरकार करती है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस नहीं दिया। मंडी टैक्स हटाने कहा था, लेकिन बढ़ा दिया। गरीबों के आवास के मामले में उन्होंने कहा कि यहां पर तो राज्य का जो हिस्सा था, वह भी राज्य सरकार नहीं दे रही। उन्होंने युवाओं सहित सभी से आग्रह किया कि भू-पे लिंक से जुड़कर भूपेश बघेल सरकार के कारनामों को सबके सामने लाएं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। उस समय मध्यप्रदेश ही बीमारू राज्य था तो समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला तो हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए। लेकिन पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया। छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और, यह तो होना ही था।जब किसी ने गंगाजल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे लेकिन घर-घर शराब पहुंचा दी। समझ सकते हैं एक तरफ मोदी जी ऑपरेशन गंगा चला कर यूक्रेन से 23000 युवा भारतीयों को सुरक्षित भारत ले आये और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगाजल की कसम खाकर क्या कर रहे हैं? दिल्ली राज्य में 200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ तो वहां के मंत्री नेता जेल में हैं। यहां 2000 करोड़ का घोटाला हुआ तो समझ सकते हैं कि इनका क्या होगा?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार तो दिया नहीं। केवल बेरोजगार बनाया। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। उन्होंने इलाज के अभाव में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में करीब 39000 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की भी मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होता है। यहां तो कांग्रेस के भू-पे राज में 39000 बच्चों की मृत्यु इलाज के अभाव में हुई।

कांग्रेस शासन में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी और लबारी - डॉ. रमन*

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मीडिया संवाद सह एप लांच कार्यक्रम में कहा कि भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाने इस एप को आज भाजपा ने लांच किया गया। 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाया है। कांग्रेस के घोटालों की सूची बहुत लंबी है। पीएससी में 18 पदों पर हुई नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। प्रदेश के युवाओं को महादेव एप के जरिये जुआ सट्टा में झोंका जा रहा हैं। पहले कांग्रेसी नारा लगाते थे छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, पर अब यह बदल गया हैं, उसकी जगह अब चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी और लबारी का नारा लगने लगा है।

प्रधानमंत्री आवास के विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को केवल सूची बना कर देनी थी। चार बार रिमाइंडर लेटर मुख्य सचिव एवं पंचायत सचिव को केंद्र सरकार ने भेजा परंतु एक भी बार इसका जवाब नहीं दिया है। यदि समय पर जवाब दे दिया जाता तो आज गरीबों को पक्का मकान मिलता। आज समय निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री आवास योजना लाए, लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है अब कोई काम नहीं हो सकता। भूपेश बघेल ने गरीबों का आवास का हक छीना है ।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स में भारत को 81 पदक जीतने पर खिलाड़ियों के साथ ही केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दो परिवर्तन यात्रा निकाली गई और यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ।

भू-पे एप लॉन्च

मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज रायपुर के एक होटल में भ्रष्टाचार स्कैनर भू-पे एप लॉन्च किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लड़ने बीजेपी की ये अहम रणनीति मानी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि वो इस स्कैनर के जरिए भूपेश बघेल सरकार के सभी भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस एप को लॉन्च करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भू-पे एप बनाया है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी।

एंटी टेरर एजेंसियों को क्रूर होना होगा : अमित

■ **शाह बोले- नहीं खड़ा होने दें कोई नया आतंकी संगठन**

नईदिल्ली। दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें न केवल आतंकवाद बल्कि उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना होगा। सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को ऐसा क्रूर दृष्टिकोण अपनाना होगा कि नए आतंकवादी संगठन न बन सकें। हमें न केवल आतंकवाद से लड़ना है बल्कि इसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट करना है और इसके लिए हमें पूरी सरकार और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना होगा।

अमित शाह ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ का काम केवल जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने चाहिए। इससे पहले आज, शाह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण है।

मोदी सरकार हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित %तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन% का उद्घाटन के साथ ही उन्होंने देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के पीछे मोदी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।

यूके में विरोध-प्रदर्शन, कनाडाई राजनयिक उपस्थिति, अफगान मुद्दा

कनाडा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि समानता पर चर्चा पर यहां राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति या हमारे आंतरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप को देखते हुए, हमने अपनी-अपनी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इसे हासिल करने के लिए चर्चा चल रही है। यह देखते हुए कि कनाडाई राजनयिक उपस्थिति अधिक है, हम मानेंगे कि कमी होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूके में 2 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और हमने निश्चित रूप से वहां राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा पर अपनी चिंताओं को यूके के अधिकारियों के साथ उठाया है। यह एक सतत बात रही है। मुद्दा सुरक्षा के बारे में है यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारे राजनयिक सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम हैं और हमारे परिसर सुरक्षित हैं।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में सदियों से अनेक जनजातीय समुदाय निवासरत हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। आदिवासियों के विरासत में आस्था का केन्द्र देवगुड़ी-मातागुड़ी है, जिसकी जनजातीय समुदायों में अपनी महत्ता है। राज्य शासन की मंशानुरूप देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न मदों के अभिसरण से इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार करने सहित उन्हें संवारने के लिए व्यापक पहल की गई है।

प्रमुख समाचार

कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को संजय सिंह को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा दिनभर चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है।

ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। कोर्ट के अंदर जाते हुए संजय सिंह ने कहा था कि यह अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। संजय सिंह के वकील ने अदालत से कहा कि आप नेता को ईडी ने अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने मीडिया से कहा कि कोर्ट ने आज दलील पर विचार करने के बाद संजय सिंह को उनके द्वारा मांगे गए दस दिनों में से पांच दिन की रिमांड दे दी है। ये आधार हास्यास्पद हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है।

भारत के लिए शानदार रहा 12वां दिन, 100 का आंकड़ा होगा पार

नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 का 12वां दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारत ने आज तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। इसके

साथ ही भारत के कुल पदों को की संख्या 86 हो गई है। भारत फिलहाल पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। चर्चा इस बात पर है कि क्या भारत पदक तालिका की अपनी संख्या को 100 तक पहुंचा सकता है? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस बार के एशियाई गेम्स में स्वर्णिम रहेगा। दिन की शुरूआत शानदार रही। भारतीय महिला कंपाउंड टीम को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता लेकिन सौरव घोषाल को रजत से संतोष करना पड़ा। पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रणय ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का किया वहीं सिंधू हार गई। अंतिम ने कांस्य जीता। वहीं, चीन से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम का स्वर्ण जीतने का सपना टूट गया।

कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था मिजोरम

मिजोरम। मिजोरम जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वह अब मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा शासित है। लेकिन धीरे-धीरे ईसाई बहुल पहाड़ी

राज्य में भाजपा भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। भूमिगत संगठन से राजनीतिक दल बना मिजो नेशनल फ्रंट साल 1987, 1998, 2003 में मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीते हैं। जबकि साल 2008, 2013, 1993 और 1989 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 1993 में दिग्गज कांग्रेस नेता ललथनहवला ने जनता दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। वहीं साल 1998 में पार्टी अध्यक्ष ज़ोरमथांगा के नेतृत्व में स्न्न ने सत्ता हासिल की और मिज़ो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन स्थानीय पार्टी ने कुछ समय बाद ही सरकार से नाता तोड़ लिया। साल 1998 और 2018 को छोड़कर कांग्रेस के दिग्गज लाल ललथनहवला ने सभी चुनावों में जीत हासिल की थी। साल 2018 में ललथनहवला राज्य के सीएम थे, लेकिन वह अपने गृह क्षेत्र सेरछिप और चम्फाई दक्षिण दोनों से हार गए थे।

भाजपा को इस बार लोस चुनाव में मेनका-वरूण मंजूर नहीं

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में एक-एक सीट का बारीकी से आकलन कर रही है। कई सांसदों के टिकट कटने

की खबर है, वहीं सबसे अधिक चर्चा मेनका गांधी और वरुण गांधी की हो रही है। जिनके बारे में अब लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी आलाकमान मॉ-बेटे दोनों का टिकट काटने जा रहा है। संभवता अब गांधी परिवार बीजेपी के लिए अप्रसांगिक हो गया है। वैसे कहा यही जा रहा है कि मेनका गांधी का टिकट उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए काटा जा रहा है, वहीं वरूण गांधी को इस लिए साइड लाइन किया जा रहा है क्योंकि वह लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हाल ही में वरूण गांधी ने रायबरेली के संजय गांधी हास्पिटल को बंद करने के योगी सरकार के फैसले के जिस तरह से मुहिम चलाई उसके बाद वरूण गांधी और बीजेपी के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई हैं। इस अस्पताल में सही से इलाज नहीं मिलने के कारण एक महिला की मौत के बाद इसको बंद करने का फैसला लिया गया था।

महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कपिल शर्मा पर ईडी का शिकंजा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरेशी को तलब किया है। अभी तक तो रणबीर कपूर से इस केस में पूछताछ होनी थी, लेकिन अब हुमा कुरैशी, जानेमाने कॉमेडियन कपिल शर्मा और टीवी एक्ट्रेस हिना खान का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। महादेव बेटिंग ऐप केस में इन तीन सेलेब्स से भी ईडी पूछताछ करेगी। हाल ही में ईडी ने 4 अक्टूबर यानी बुधवार को रणबीर को समन भेजकर 6 अक्टूबर को रायपुर, छत्तीसगढ़ में एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था, हालांकि लेटेस्ट खबर के मुताबिक रणबीर ने ईडी को मेल कर 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने यूएई के रास अल-खैमा में शादी है। आरोप है कि इस शादी में महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए.परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराये पर लिए गए थे। इस शादी में नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था। ईडी के अनुसार, इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया था। डिजिटल सबूतों के आधार पर ईडी ने दावा किया है।

न्यूजक्लिक को चीन से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप, देश विरोधी चलाया एजेंडा

अभिनय आकाश

3 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में लगभग नौ घरों में पुलिस छापा मारने के इरादे से दाखिल हुई। ये नौ लोग पत्रकार, लेखर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सभी एक न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े हुए थे। न्यूजक्लिक पर बीते दिनों आरोप लगे कि उसने चीन से पैसा प्राप्त कर भारत विरोधी और चीन के समर्थन में प्रचार किया। इनके केंद्र में इंफोर्समेंट डॉयरेक्टरेट यानी ईडी और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। कई रिपोर्टों के अनुसार, न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूज़क्लिक उन संगठनों में से एक था, जिनके खिलाफ 17 अगस्त को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से चीनी प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए।

दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए चीन से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है। समाचार पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती को संगठन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा

राष्ट्रीय राजधानी में 88 स्थानों और न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों सहित अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई। ये दिन भर की छापेमारी अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज़क्लिक उन संगठनों में से एक था, जिन्हें चीनी प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज नेविल रॉय सिंघम से पैसे मिले थे।

अधिकारियों का आरोप है कि न्यूज़क्लिक यह दिखाने की साजिश में लगा हुआ है कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि गुप्त इनपुट से पता चला है कि पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम और सिंघम के स्वामित्व वाली शंघाई स्थित कंपनी के कुछ अन्य चीनी कर्मचारियों ने मेल का आदान-प्रदान किया है। जो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने के उनके इरादे को उजागर करता है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ई-मेल के विश्लेषण से पता चला है कि सिंघम, पुरकायस्थ और चक्रवर्ती एक दूसरे के साथ 卐सीधे संपर्क卐 में हैं और उन्होंने चर्चा की थी कि कश्मीर के बिना भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में कैसे दिखाया जाए। पुलिस ने दावा किया कि इसके लिए आरोपियों को विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपये से अधिक मिले।

चीन से फंडिंग

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि एम/एस पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को अप्रैल 2018 से करोड़ों रुपये प्राप्त हुए। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार समाचार वेबसाइट (न्यूज़क्लिक) को चीन से धन प्राप्त हो रहा था। उन्हें शंघाई स्थित अमेरिकी व्यवसायी, नेविल रॉय सिंघम से धन प्राप्त हुआ। उन्होंने अशांति पैदा करने के लिए भारत की छवि खराब करने के लिए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बारे में एक तयशुदा कहानी के साथ कहानियां प्रकाशित कीं। रिमांड आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 卐गुप्त इनपुट प्राप्त हुए हैं कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है।

न्यूज़क्लिक की प्रतिक्रिया

न्यूज़क्लिक ने अपने बयान में कहा कि वह प्रचार प्रकाशित नहीं करता है और इसकी फंडिंग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। समाचार पोर्टल ने 4 अक्टूबर को कहा कि न्यूज़क्लिक को प्राप्त सभी फंडिंग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई है और कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है।

गोरकापार के ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

■ बोले- पहले पूरी करनी पड़ेगी मांग

बालोद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बालोद जिले में तैयारी जोरों पर हैं। वहीं, गोरकापार गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की मांग है कि उनका गांव ग्राम पंचायत चीचा का आश्रित गांव है। उसे स्वतंत्र पंचायत का दर्जा दिया जाए। गुरुवार को अपना काम बंद करके सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने अलग पंचायत की मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव आदिवासी बाहुल्य गांव है और अनुसूचित जनजाती वर्ग की उपेक्षा इस गांव में हो रही है।

राज्य बनने से आज तक नहीं हुआ विकास

ग्रामीण अनिल मानकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनका गांव आदिवासी बाहुल्य होने के बाद भी विकास कार्यों से कोशों दूर हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम गोरकापार में आने जाने के लिए एक ही मार्ग है और वह भी जर्जर अवस्था में है। बीच में एक नाला पड़ता है और वह हर वर्ष बरसात के पानी में बह जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है।

शिक्षा के लिए दूसरे गांवों पर रहना पड़ता आश्रित

ग्रामीण महाजन सिंह ठाकुर ने बताया कि गांव में केवल प्राथमिक स्तर तक ही स्कूल है। उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव पर आश्रित रहना पड़ता है। आश्रित गांव होने के कारण आदिवासी बाहुल्य लोग होने के कारण यहां पर विकास रुका हुआ है। सिंचाई के लिए नहर नाली की व्यवस्था का भी अभाव है। जिसके कारण कृषि उत्पादन में गांव पिछड़ा हुआ है।

सचिव पटवारी तक नहीं आते गांव

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पंचायत सचिव, पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी झांकने तक नहीं आते। कृषि विस्तार अधिकारी का चक्कर काटना पड़ता है, जिसके कारण वे सब काफी परेशान हैं। गांव में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो इलाज के लिए भी दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गांव में जानवरों के लिए गठन की सुविधा नहीं है।

हर क्षेत्र में विकास से दूर

ग्रामीणों ने बताया कि इन सब पिछड़ेपन और विकास से दूर रहने का एकमात्र कारण यह है कि वह किसी अन्य पंचायत का आश्रित गांव है। बिजली के खंभे जर्जर होकर टूट रहे हैं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए सभी जिला प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। खेतों में आने-जाने के लिए सड़के नहीं हैं। मुक्तिधाम में शेड का निर्माण नहीं कराया गया है।

जनप्रतिनिधि नहीं देते ध्यान

ग्रामीणों ने पूरे मामले में पूर्व विधायकों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखित शिकायत पत्र में लिखा है कि गांव में पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू राजेंद्र राय एवं वर्तमान विधायक कुंवर सिंह निषाद को भी समस्या से अवगत कराया गया था। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधी द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए वे जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

दो कांग्रेस पदाधिकारी एक साल के लिए निलंबित, अभद्र टिप्पणी का आरोप

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। अनुशासनहीनता पर जिला कांग्रेस कमेटी ने दो कांग्रेस पदाधिकारी को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोनों पदाधिकारियों पर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध लगातार अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला महामंत्री ने एक वर्ष के लिए निलंबित किया है।

अनुशासनहीनता पर लगातार जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन ने सोशल मीडिया प्रभारी और एक कांग्रेस के पदाधिकारी को कांग्रेस नेताओं पर अभद्र टिप्पणी के साथ सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट डालने पर दोनों पदाधिकारी घनश्याम सिंह ठाकुर मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी एवं आमिर अली कांग्रेस पदाधिकारी पर निलंबन की कार्यवाई की है।

जिला कांग्रेस कमेटी ने उक्त दोनों पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिस पर दोनों पदाधिकारियों ने नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया ना ही उसका जवाब ही दिया। जिसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्तम वासुदेव के निर्देश पर जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह ने उक्त दोनों पदाधिकारियों को एक वर्ष के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से निलंबित कर दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि एक अक्टूबर को एक निजी कार्यक्रम में मरवाही विधायक के के ध्रुव के विरुद्ध अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले चार कांग्रेस नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो कांग्रेस संगठन पर चर्चा का विषय बना हुआ था। देर शाम दो कांग्रेस नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई से संगठन अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात का प्रमाण जिला कांग्रेस कमेटी ने देखकर अनुशासन की लकीर खींची।

आरी के साथ हाथी की यारी, छत्तीसगढ़ में है इस बार तीसरे मोर्चे की तैयारी

कोरबा। छत्तीसगढ़ में जब भी तीसरे मोर्चे की बात हुई है तब किसी मजबूत पार्टी का नाम सामने नहीं आया। सवाल यह है कि क्या इस बार ये धारणाएं बदल जाएंगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के पदाधिकारी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। गठबंधन के बाद इनका दावा है कि उनके सहयोग के बिना इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दावों में कितना दम है और क्या सच में छत्तीसगढ़ में इस बार तीसरा मोर्चा शक्तिशाली साबित होगा।

छत्तीसगढ़ में गोंगपा और बसपा दोनों ही पार्टियों का जनाधार तो है। जानकर भी यह बात स्वीकार करते हैं कि भले ही इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन इतने वोट वह जरूर हासिल लेते हैं, जिससे कि किसी की हार तय हो जाती है। कोरबा के पाली तनाखार सीट पर अक्सर गोंगपा सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम चुनाव लड़ते रहे हैं। यहां से वह एक बार विधायक भी रहे और पिछले कई चुनाव में भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलते रहे हैं। अब वह इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम पाली से चुनाव लड़ेंगे। जबकि बसपा की बात की जाए तो कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में इनका अच्छा खासा जानाधार है। जांजगीर-चंपा के पामगढ़ सीट से बसपा के विधायक भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कई सीटों पर दोनों पार्टियों का ठीक-ठाक वोट बैंक है। जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस जैसे पार्टियों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कोरबा में बसपा के जिलाध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने बताया कि 25 सितंबर को हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में गठबंधन तय हो चुका है। पदाधिकरियों ने मिलकर यह तय किया है कि प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। 53 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतरेगी। जबकि 27 सीट पर गोंगपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। पाली से हीरासिंह मरकाम के बेटे और गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पर नाम की घोषणा भी जल्दी ही होगी। 6 सितंबर को रायपुर में दोनों पार्टियों के संयुक्त बैठक होनी है। उम्मीद है कि इस दिन प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में गोंगपा का अच्छा खासा जनाधार है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग की सीटों पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वह भले ही किसी सीट पर चुनाव ना जीतें, लेकिन किसी प्रत्याशी की हार में कारगर भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से कोरबा के पालीतानाखार विधानसभा सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर खिसकी हुई है। पिछले तीन चुनाव से भाजपा की लगभग यही स्थिति रही है। पाली तानाखार विधानसभा सीट के अलावा भरतपुर सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, प्रतापपुर, मरवाही और कोटा की सीटों पर गोंगपा का प्रभाव है। विधानसभा चुनाव 2018 में इन 8 विधानसभा सीटों पर वोटर्स की कुल संख्या 14 लाख 64 हजार 234 थी। जिसमें से 10 लाख 98 हजार 168 वोट आदिवासियों के थे। गोंगपा पार्टी को इस चुनाव में इन 8 विधानसभा सीटों में 2 लाख 30 हजार वोट मिले थे। इन सभी सीटों पर आदिवासी वोटर्स की संख्या 75 प्रतिशत या इससे ज्यादा है।

बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान सुप्रीमो मायावती यूपी से हैं। लेकिन इस पार्टी के संस्थापक काशीराम ने पहला चुनाव जांजगीर लोकसभा सीट से लड़ा था। तब कोरबा लोकसभा सीट का गठन नहीं हुआ था। कोरबा जिला जांजगीर लोकसभा सीट में ही शामिल था। कांशीराम पहला चुनाव हार गए थे। इसके बाद वह यूपी चले गए, और मायावती से मिले। अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने मायावती को ही सौंप दी। बसपा की स्थापना कोरबा जिले में ही हुई थी। यहीं से पार्टी की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में अब अब भी पार्टी का जनाधार मौजूद है।

नक्सलियों के कब्जे में बस्तर फाइटर का लापता जवान

बीजापुर। बस्तर फाइटर के जवान शंकर कुड़ियम के अपहरण की जिम्मेदारी माड़ डिवीजन के नक्सली संगठन ने ली है। नक्सलियों ने जवान के अपहरण को लेकर माड़ डिवीजन कमेटी की सचिव अनीता मंडावी की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया है।

नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट

प्रेस नोट में नक्सलियों ने लिखा है कि उनके कब्जे में 29 सितंबर से बस्तर फाइटर का जवान शंकर कुड़ियम है।जिसकी जानकारी पुलिस परिजनों से छिपा रही है। संगठन ने प्रेस नोट में लिखा है कि फिलहाल जवान से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में पुलिस की प्रतिक्रिया के आधार पर संगठन के फैसला लेने की बात प्रेस नोट में लिखी है।

क्या है नक्सलियों की मांग ?

जो प्रेस नोट नक्सली संगठन की ओर से जारी किया गया है उसमें ताड़मेटला कांड में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और सजा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ऐसी सूचना है कि नक्सलियों ने बस्तर फाइटर के एक जवान का अपहरण कर लिया है।जिसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं हुई है।

कैसे हुआ अपहरण ?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एरमनार निवासी कुडियम शंकर बीजापुर पुलिस लाइन में तैनात है। कुछ दिन पहले कुड़ियम शंकर भैरमगढ़ ब्लॉक के उसपरी गांव हुआ था। वहीं से नक्सलियों की एक टीम ने जवान को अगवा कर लिया।वहीं जवान पिछले माह की 27 से 28 तारीख की ड्यूटी में भी नहीं गया। हालांकि जवान के अपहरण होने की जानकारी परिजनों ने थाने में नहीं की है।वहीं परिवार नक्सलियों से जवान को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। मीडिया में जब इस बात की जानकारी लीक हुई तो नक्सलियों ने अब प्रेस नोट जारी कर जवान के अपहरण की बात स्वीकारी है।लेकिन पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

बेमेतरा जिले में छह लाख से ज्यादा मतदाता, यही चुनेंगे अपना विधायक

बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस एल्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जिले के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, जिले में 6 लाख 58 हजार 593 मतदाता हैं। इनमें 3 लाख 31 हजार 143 पुरुष मतदाता, 3 लाख 27 हजार 446 महिला मतदाता हैं।

वहीं थर्ड जेंडर के चार मतदाता है। निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बाद जिले में 18-19 आयु वर्ग के 32,205 मतदाता बढ़े हैं। इनमें 17984 युवक मतदाता और 14221 युवती मतदाता हैं। बैठक में बताया गया कि आम जनता, मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित जनपद में भी सूचना पटल पर चस्पा कराया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस एल्मा ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 867 मतदान केन्द्र हैं। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा के क्रमों 202 से 302 तक कुल 101 मतदान केन्द्र दुर्ग जिला में शामिल हैं। इसी प्रकार विधानसभा बेमेतरा के मतदान केन्द्र क्रेमों 197 से 218 तक कुल 22 मतदान केन्द्र दुर्ग जिला में शामिल हैं।

इन केंद्रों के अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जिला दुर्ग में हुआ है। उन केन्द्रों के मतदाता की संख्या उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान कुल 65 हजार 949 फॉर्म में से 59 हजार 938 फार्म वोटर हेल्प लाइन एप्प एवं वोटर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए शेष हार्ड कॉपी में आए। कलेक्टर ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा, साजा और नवागढ़ के मतदान केंद्रों की संख्या, मतदान केंद्र की वृद्धि और मतदान केंद्र भवन में हुए परिवर्तन आदि की जानकारी से अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जैतखाम निर्माण की मिली सौगात, कलेक्टर ने दी बधाई

मुंगेली। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार अक्तूबर को रायगढ़ के कोड़ातराई में आयोजित कार्यक्रम में बाबा गुरू घासीदास के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 82 चयनित विकासखण्डों में बनने वाले जैतखाम का वर्चुअल शिलान्यास किया। जिसमें मुंगेली जिला में तीन जैतखाम के निर्माण हेतु शिलान्यास भी शामिल है। इस अवसर पर जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर राहुल देव, अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले, नगर पंचायत पथरिया के अध्यक्ष ग्वाल दास अनंत, गणमान्य नागरिक दुर्गा बघेल, रेखचंद कोशले, रूपलाल कोसरे सहित समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। कलेक्टर राहुल देव ने जैतखाम शिलान्यास के लिए समाज के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जैतखाम निर्माण के लिए 25-25 लाख रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित स्थान ऐसी होनी चाहिए जहां से जैतखाम आकर्षक एवं भव्य नजर आए।

बिना सुरक्षा उपकरण के काम करते हैं कर्मचारी

जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के चिंगपाल में बिजली खंभे पर चढ़ा युवक ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से चिपक गया। जिससे वह बुरी तरह से जल गया। घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती कराया गया। घायल करीब 36 से 40 प्रतिशत के बीच जल गया था। मामले के बारे में घायल के साथियों ने बताया कि धमतरी जिले के नगरी सिहावा में रहने वाला मनीष नेताम 18 वर्ष अपने आठ साथी, जिसमें झुमुक निषाद, विभीषण, मनीष कुमार, राहुल, राजू के अलावा अन्य साथी सीएसपीडीसीएल के द्वारा बिजली का काम करने के लिए आए हुए थे। चिंगपाल में मनीष नेताम अपने साथियों के साथ ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ना था। साथियों ने मुख्य ऑफिस में बैठे ऑपरेटर को लाइन बंद करने की बात कही। ऑपरेटर ने बिना मुख्य लाइन को बंद किए ही लाइन बंद होने की बात कही। जिसके बाद मनीष नेताम जैसे ही ट्रांसफार्मर की बाईन्डिंग करने के लिए जैसे ही खंभे को पकड़ा तो करेंट लगने के बाद युवक झुलस गया।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पर बालोद पुलिस

बालोद। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बालोद में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। लगातार गुंडे बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो आदतन अपराधी हैं। उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है। बालोद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि चुनावी समय में हम शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करना चाहते हैं। ऐसे में यदि कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी थाना चौकी में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना उनका लक्ष्य है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नए और पुराने सभी गुंडों और बदमाशों की फाइल खोली जा रही है। ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और गुंडे बदमाशों की निगरानी भी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर मौके पर कार्रवाई की जा रही है।

पीएससी मामले में सरकार को 10 दिन का अतिरिक्त समय

बिलासपुर। पीएससी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। भाजपा सरकार ने गृहमंत्री रहे ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ पीएससी में बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की याचिका पर पीएससी और राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि वो स्वयं जांच करने के बाद न्यायालय के सामने जवाब पेश करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई जब तक नहीं हो जाती, तब तक जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। उन्हें अंतिम रूप नहीं दी जाएगी। वहीं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनकी नियुक्ति पर यथास्थिति न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगी।

नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते 35 ट्रेनें रद्द

बिलासपुर। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव-कलमना रेल खंड के बीच में तीसरी लाइन को आमगांव रेलवे स्टेशन से जोडने का कार्य किया जाएगा। सात से 10 अक्टूबर प्री और 11 से 14 अक्टूबर नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते अलग-अलग तिथि में 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें शिवनाथ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस व बिलासपुर- पुणे एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। अन्य जोन के अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अलग- अलग सेक्शनों में अधोसंरचना से जुड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण काम है। इसकी वजह से यात्रियों को अभी परेशानी हो रही है। लेकिन, जब सभी रेलवे में कार्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। रेल प्रशासन का यही मानना है। हालांकि यात्रियों की माने तो अधोसंरचना का कार्य करना सही है। लेकिन, इसे पूरी योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। वर्तमान में चारों दिशाओं की अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके कारण यात्रियों के लिए ट्रेन सुविधा नहीं मिल पा रही है।

लुंड्रा सीट पर विधायक डॉ. प्रीतम राम के परिवार का दबदबा

अंबिकापुर। सरगुजा में एक ऐसा परिवार है, जिसके सदस्य 6 बार विधायक रहे हैं और अब 7वीं बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। परिवार के 3 सदस्य दो-दो बार विधायक रहे हैं। यह कहानी है जिले के लुंड्रा विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉ प्रीतम राम के परिवार की। डॉ प्रीतम राम फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।

लुंड्रा के गांव गगोली में रहने वाले आदिवासी समाज के चमरू राम 1967 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बने। इसके बाद 1972 में चमरू राम दोबारा विधायक बने। इनके बाद इनके बेटे रामदेव राम भी कांग्रेस की टिकट से 1998 में चुनाव लड़े और विधायक बने। रामदेव राम 2008 का विधानसभा चुनाव भी जीते। चमरू राम के बड़े बेटे पेशे से डॉक्टर थे। वो बलरामपुर के राजपुर में बीएमओ के पद पर पदस्थ थे। 2013 में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस की टिकट से बलरामपुर के सामरी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। 2018 में एक बार फिर कांग्रेस ने इन्हें लुंड्रा से टिकट दिया और डॉ प्रीतम राम ने लुंड्रा से विधायक चुने गए। पूर्व विधायक और इनके भाई रामदेव राम वर्तमान में सहकारी बैंक सरगुजा के अध्यक्ष हैं।

लुंड्रा विधानसभा में वर्तमान विधायक डॉ प्रीतम राम के परिवार का दबदबा रहा है। 1967 से लेकर अब तक इनके परिवार के 3 सदस्य 6 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले 1967 में चमरू राम ने कांग्रेस के टिकट पर लुंड्रा से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। उन्होंने 1972 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज किया और दूसरी बार विधायक चुने गए। 1998 के विधानसभा चुवान में चमरू राम के बेटे रामदेव राम ने कांग्रेस के टिकट पर नमैंदान में उतरे और विधायक चुने गए। 2008 में भी रामदेव राम ने जीत दर्ज की। जिसके बाद 2013 में चमरू राम के बड़े बेटे डॉ प्रीतम राम ने कांग्रेस की टिकट पर सामरी से जीत दर्ज की। वहीं 2018 में डॉ प्रीतम राम को फिर लुंड्रा सीट पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा और वे विधायक चुने गए।

राजनीतिक विश्लेषक मनोज गुप्ता कहते हैं कि क्षेत्र में जातिगत समीकरण के साथ ही इस परिवार का स्वभाव बहोत सामान्य है। इनके पिता हों या रामदेव राम या फिर प्रीतम राम सभी का स्वभाव बेहद नरम है। कभी भी किसी घोटाले से इनका नाम नहीं जुड़ा है। यही कारण रहा कि क्षेत्र में लोग इनको पसंद करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये परिवार कांग्रेस और सिंहदेव परिवार के साथ हमेशा ही खड़ा रहा। इसलिए कांग्रेस ने भी इन पर भरोसा दिखाया है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जेपी श्रीवास्तव कहते हैं, लुंड्रा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया है। यही कारण है कि प्रीतम राम उनके भाई और उनके पिता भी विधायक रहे हैं। इन लोगों का क्षेत्र में बर्ताव बहुत अच्छा रहा है। सहजता से सबसे मिलते हैं, जिसका फायदा मिलता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 इस साल के अंत में होने हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के लिए पार्टी की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस बार लुंड्रा विधानसभा से फिर डॉ प्रीतम राम को टिकट मिलने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में जगह बनाना चाहती है आप

कोरबा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अमृतपाल सिंह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दौरे पर हैं। वे अपनी पार्टी की नींव मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में अमृतपाल सिंह कटघोरा विधानसभा पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के कोरबा जिलाध्यक्ष द्वारा कटघोरा नगर में विशाल रैली निकाली और जनसभा का आयोजन किया।

प्रदेश सह प्रभारी अमृतपाल सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, लेकिन यहां के लोगों को क्या मिला? वही खराब सड़क, न अच्छा स्कूल दे पाई और न अच्छे कॉलेज दे पाई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ही तीसरा विकल्प बन गया है और लोगों में पार्टी को लेकर उत्साह है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब पहले की तरह नहीं रहीं हैं। महिलाएं अब पढ़ी, लिखी और एजुकेटेड हैं। उनको पता चल गया है कि उनके अधिकार क्या हैं, अब वो साड़ियों के पीछे, दारू के पीछे नहीं जाएंगी। इस बार मुद्दों की राजनीति होगी।

प्रदेश सह प्रभारी अमृतपाल सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता ने बीजेपी को चुना, जिससे तंग आकर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार भी छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता के साथ छलावा कर रही है। किसानों और बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। आज किसान परेशान है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत बद से बदतर है। जनता परिवर्तन चाहती है, आने वाले समय में निश्चित ही परिवर्तन होगा।

भूपेश के चेहरे पर होगा चुनाव, कांग्रेस की होगी वापसीः शर्मा

देश को गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल की जरूरत

अंबिकापुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह विधायक और पार्टी हाईकमान तय करेंगे। भाजपा के सांसद डरे हुए हैं कि पार्टी उन्हें कैलाश विजयवर्गीय की तरह जबरदस्ती विधानसभा का टिकट न थमा दे। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी।

दरअसल अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश को गुजरात नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पांच सालों में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां देश में किसानों को धान की सर्वाधिक कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है। गुजरात मॉडल में सिर्फ दो लोगों का विकास हुआ है।

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी में जितना घोटाले का आरोप

लगाया जा रहा है, उतना का गोबर ही नहीं खरीदा गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 65 से अधिक अवार्ड दिए हैं, और वे यहां आकर बदलाव की बात करते हैं।

आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता साढ़े चार साल तक अपने 15 वर्ष के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मुंह छिपाए हुए थे। भाजपा शासन काल में स्कूल बंद होते हैं, हमने नए स्कूल खोले। आत्मानंद योजना के तहत 700 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? यहां जनता परिवर्तन नहीं चाहती है।

टीएस सिंहदेव ने किया अतिथि परंपरा का पालन

डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रायगढ़ की जनसभा में पीएम मोदी की तारीफ की थी। जिसे लेकर आलोक शर्मा ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ की अतिथि देवो भवः की परंपरा का पालन किया। हम अपने घर आए, अपने मंच में आए किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते। इसी परपंरा का निर्वहन उन्होंने किया है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। यही डिप्टी सीएम कार्यक्रमों में भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हैं।

घोटालों के सबूत हैं तो न्यायालय में दें

आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। सिर्फ आरोप लगा देना भाजपा, आरएसएस और नेताओं की नीयती बन गई है। उनके पास सबूत है तो वे न्यायालय में दें, जांच एजेंसियों को दें। यदि उनके आरोपों में दम होता तो उनकी परिवर्तन यात्रा फ्लाप नहीं होती।

पीएससी विवाद पर बोले- गलत करने वालों का पक्ष नहीं

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट किया है कि गलत काम करने वालों पक्ष नहीं लेंगे। यदि किसी ने गलत किया है तो कांग्रेस उसका पक्ष नहीं लेगी। किसी के पास सबूत हैं तो वे व्हीसिल ब्लोअर बने, न्यायालय में सबूत दें। उनका स्वागत करेंगे। कानूनी प्रकिया में सरकार बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। व्यापमं की तरह उसे दबाया नहीं जाएगा। व्यापमं की तरह जांच अधिकारियों की हत्याएं नहीं होंगी। दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।

भाजपा ने रोका है जातीय जनगणना

देश में जातीय जनगणना को लेकर आलोक शर्मा ने कहा कि देश में जातीय जनगणना की कांग्रेस पक्षधर है। 2011 में यूपीए के शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी। यूपीए की सरकार गिरने के बाद भाजपा सरकार ने उसे दबा दिया। भाजपा के लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वे ही कोर्ट में आपत्ति करते हैं। जातीय जनगणना से जातिवार आरक्षण का सही लाभ उन वर्गों को मिल सकेगा।

कनाडा के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा के देश की अखंडता के मुद्दे पर कांग्रेस मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को ज्यादा पारदर्शिता रखना चाहिए ताकि अन्य देशों के समक्ष भारत का पक्ष और मजबूत हो। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी।

देश में स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से रही है बढ़ः डा. मंजू

रायपुर। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर के सबसे गंभीर प्रकारों में से एक है। देश में स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर कैंसर के प्रारंभिक चरण में इसका पता चल जाए तो इसका उपचार संभव है। ब्रेस्ट में होने वाली गांठ स्तन कैंसर के सामान्य लक्षण है। स्तन के आकार या आकार में बदलाव, निपल डिस्चार्ज, स्तन पर त्वचा में परिवर्तन, जैसे रेडनेस या सिकुडन, लगातार स्तन में दर्द या बेचैनी आदि इसके लक्षण है। नियमित व्यायाम और फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार के साथ स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना इससे बचने के उपाय हैं । उक्त बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की विभाग अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ़ सर्जरी व प्रोफेसर डॉ. मंजू सिंह ने कहीं।यह आयोजन गुरुकुल महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी में लायंस क्लब रायपुर समर्पण द्वारा ब्रेस्ट कैंसर पर जागृति लाने के लिए एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाइंस क्लब रायपुर से अध्यक्ष श्रीमती सुलेखा मुखर्जी, चैप्टर प्रेसिडेंट डॉ संगीता नेरल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता, श्रीमती भावरा, श्रीमती सीमा गुप्ता तथा श्रीमती सुजाता भटनागर उपस्थिति रही। महाविद्यालय की छात्राओं एवं प्राध्यापकों के लिए यह व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इस अवसर पर छात्राओं ने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किये।

संक्षिप्त समाचार

नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महा-सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी

रायपुर। चुनाव आचार संहिता लगने में अब महज कुछ ही दिन शेष हैं इस बीच राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से दस्तक देने के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार, 6 अक्टूबर को अयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महा- सम्मेलन में शरीक होने के लिए रायपुर आ रही है। अल्पसमय में प्रियंका गांधी का यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। दूसरी बार वह आदिवासी अंचल के कांकेर जिले गोविंदपुर मैदान में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महा- सम्मेलन में शामिल होंगी और सभा को संबोधित करेंगी।

सभापति दुबे ने 136 हितग्राहियों को वितरण किया पट्टा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भरोसे की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गाँधी आश्रय योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आवासहीन गरीबों को आवासीय पट्टे का वितरण करवाकर आमजनों से किया अपना वायदा पूरा कर दिखाया है। इसी सिलसिले में श्री दुबे ने पण्डित भगवती चरण शुक्ल वार्ड के आनंद 136 पात्र आवासहीन गरीबों को योजना के तहत आवासीय पट्टे वितरित किये। इससे प्रसन्न सभी सम्बंधित पट्टाधारी हितग्राहियों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। दुबे ने योजना के कार्य से सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वार्ड, जोन क्षेत्र सहित रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में कोई भी पात्र आवासहीन गरीब व्यक्ति राजीव गाँधी आश्रय योजना के तहत आवासीय पट्टे को प्राप्त करने से कदापि वंचित ना रहने पाये, यह सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाये।

तखतपुर में बाहरी प्रत्याशी नहीं करेंगे बर्दास्त, भाजपा अध्यक्ष को लिखा पत्र

रायपुर। बिलासपुर जिले का तखतपुर विधानसभा क्षेत्र जनसंघ के समय से लेकर अब तक भाजपा का गढ़ रहा है। अब कि बार चुनाव जीतने के लिए सभी स्थानीय नेता व कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हुए गांव-गांव पहुंच रहे हैं, ऐसे में किसी बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने की खबर से वे नाराज हो गए हैं। भाजपा के स्थानीय मंडल, मोर्चा, महिला ईकाई से लेकर एवीबीपी से जुड़े सैकड़ों लोगों ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव को पत्र लिख कर विरोध जताया है और स्पष्ट कहा कि स्थानीय स्तर पर किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दें वे पार्टी के लिए काम करने तैयार हैं लेकिन किसी बाहरी

रायपुर महिला कांग्रेस बूथों में जाकर करेंगी भूपेश सरकार की योजनाओं का प्रचार

रायपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रभारी विजया एवं मालिनी द्वारा रायपुर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी व ब्लॉक अध्यक्षो की बैठक गांधी चौक स्थित कांग्रेस भवन में हुई। इस बैठक में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की जनहितैषी कार्यों और उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने महिलाओं के आर्थिक के लिए जो योजनाएं चला रही है उससे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उन्मूलक योजनाओं को जन जन तक बूथों के माध्यम से शहर महिला कांग्रेस को पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभारियों द्वारा निर्देशित किया गया।

पूर्ववर्ती 15 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो जो बड़े बड़े कांड झलियारी कांड ,गर्भाशय कांड हुऐ जिनसे महिलाये पीड़ित हुई । उन बहनों का दर्द को समझते हुये हमारी कांग्रेस सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना,हाट बाजार क्लीनिक ,डॉ खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य योजना,मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना 25 लाख तक निशुल्क ईलाज के माध्यम से महिलाओ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की। गौधन न्याय योजना के माध्यम से महिलाओ को गौठान में आर्थिक लाभ व रोजगार मिल रहा। नये नये उत्पाद महिला बहनो के द्वारा गोबर से बनाकर विदेशों में निर्यात किया जा रहा ।बिजली बिल हाफ से भी घरों में बचत हो रही है। वही केंद्र सरकार सिलेंडर के भाव 400 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपए कर दिया जिससे आम जनता परेशान हैं। अनेक राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते

हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 200 रूपए कम कर झुनझुना दिया है। चुनाव के बाद फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 1500 रूपए हो जायेगा। वही ,पेट्रोल,डीजल ,सब्जी ,दाल, तेल,आटा, का दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। महंगाई ने महिलाओ का चूल्हा चौका चलाना मुश्किल कर दिया है।इन मुद्दों को महिला कांग्रेस जन जन तक पहुचायेगी । बैठक रायपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता शर्मा के नेतृत्व में हुई। बैठक में प्रमुख रूप से लोकसभा समन्वयक अनिता गुरूपंच, सायरा खान,चमेली रात्रे निवेदिता चटर्जी,गंगा यादव, पार्वती साहू ,मिथलेश रिछारिया पार्षद नीलम जगत, अनुषा श्रीवास्तव,लता जंघेल ,शशि शर्मा, बुधियारिन मरकाम,रिजवाना बेगम ब्लॉक अध्यक्ष गण, नीलिमा मिश्रा,संध्या ठाकुर,संगीता तिवारी,सिद्धि ठाकुर,चन्दा मिरी,नन्दा मानिकपुरी, रेखा जोशी,पार्वती शर्मा,सावित्री चन्द्रवंशी,शोभा मन्धानी सहित सैकड़ो शहर महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ महिला कांग्रेस सदस्य उपस्थित थीं।

गांव उत्पादन और शहर विपणन का केंद्र हैं अतः गांवों को स्वावलंबी होना चाहिए : बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एक निजी टीवी न्यूज चैनल के द्वारा आयोजित भरोसा अउ सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में गांवों की संख्या अधिक है और शहरों की कम है । गांव जहां उत्पादन के केंद्र हैं वहीं शहर ग्रामीण उत्पादों के विपणन का केंद्र हैं अतः गांवों को स्वावलंबी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरूआत की गयी है और वर्तमान में राज्य में 300 रीपा की स्थापना हो चुकी है जहां रोजगार के साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा के साथ युवा आनलाइन शिक्षा का भी लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है, इसके लिए पहले किसानों के कर्ज माफ किए गए और फिर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गयी। इतना ही नहीं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं थी उन्हें भी न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और 7 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग की जेब में योजनाओं के माध्यम से पैसे पहुंच रहे हैं और इसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिल रहा है , यही वो वजह थी कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का प्रभाव नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों व मजदूरों के सपने छोटे-छोटे हैं। राज्य सरकार ने योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर के 3 करोड़ लोगों के सपने सच किए हैं और इससे हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं से वर्तमान सरकार ने सरगुजा से लेकर बस्तर तक के लोगों का भरोसा जीता है।

कांग्रेस के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक डॉ. प्रसाद आज लेंगे बैठक

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक डॉ. श्रीवेल्ला प्रसाद 05 अक्टूबर गुरूवार को रात्रि 7.50 बजे नियमित विमान सेवा द्वारा हैदराबाद से रायपुर पहुंचेंगे एवं बेबीलॉन इंटरेनशनल होटल के लिये रवाना होंगे। रायपुर में रात्रि विश्राम। 6 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित पर्यवेक्षक एवं लोकसभा पर्यवेक्षक की बैठक में भाग लेंगे।

छग, मप्र व राजस्थान के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आसपा

यूज इन थ्रो की नीति से हर एक समाज का युवा हैं पीड़ित : सेठ

रायपुर। आप सबकी अपनी पार्टी (आसपा) आगामी दिनों पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा में प्रत्याशी उतारने जा रही है। आसपा छत्तीसगढ़ में लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी वहीं पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश व राजस्थान में भी सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सिर्फ युवाओं को यूज इन थ्रो की नीति केतहत उनका इस्तेमाल किया है और इससे पीड़ित हैं। लेकिन इस बार उनकी उम्मीद पर आसपा पार्टी खरी उतरेगी और अगर वे जीतकर आती है तो छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ में 365 दिन काम का मास्टर रोल दिया जाएगा इसके साथ ही शिक्षाकर्मियों का

संविलियन तत्काल प्रभाव से किया जायेगा । उक्त बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप सबकी अपनी पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सेठ ने कहीं।

उन्होंने कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलो द्वारा गुरुओं, संतो, महापुरषों की मानवतावादी विचारों, सामाजिक समस्या को दरकिनार कर किसान, मजदूरों, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यों पर लगातार शोषण किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन को बेचकर लुटने में लगे हुए है। छत्तीसगढियों का समग्र चिन्तन जरूरी है चूंकि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति सत्ता हासिल करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक परिवर्तन के साथ - साथ मान सम्मान भी हमारा लक्ष्य है। आसपा ने इन बातों पर गंभीरता से चिंतन करते हुए उनके नजदीक भावनाओं को समझने का प्रयास किया है कि करोड़ो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पूंजीपति वर्ग एवं विभिन्न राजनीति दल बड़े पैमाने पर इनका फायदा उठा रहे हैं। युवाओं, किसानों को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक उन्नति कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ युवाओं को उपयोगी सामाग्री समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज इन थ्रो अर्थात उपयोग करो और फेक दो की नीति से हर एक समाज की युवा पीड़ित है। हमारे देश का जवान सीमा में शहीद हो रहे हैं। उनकी परिवारों की सरकार को तनिक चिंता नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ीया राज लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, नशामुक्त प्रदेश बनाना है, शोषण, अन्याय, अत्याचार को समाप्त करना है तो हमें भेदभाव को भूलकर मिल जुलकर काम करना होगा।

बोनस पर प्रतिबंध हटाने भूपेश ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि किसानों से वर्ष 2013 में वायदा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया। ये राशि 3700 करोड़ रुपए की है जो अब तक किसानों को अप्राप्त है।मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की। मई 2014 में केन्द्र में सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिये जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया।किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिये जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। फलस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गये धान पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रण में आप पार्टी बढ़ाएगी भाजपा-कांग्रेस की टेंशन

रायपुर। इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ चुनाव में उतर गई है। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में नरेंद्र कुमार नाग, आनंद प्रकाश मिरी, कोमल हुपेंडी, बालो राम भवानी, विशाल केलकर, तेजराम विद्रोही, राजा राम लकड़ा, खादागरज सिंह, सुरेंद्र गुप्ता और लियोस मिंज के नाम हैं।

बता दें कि इससे पहले राज्य में पांच साल से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी ने 21 नामों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में पांच महिलाओं को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने उनके भतीजे और मौजूदा सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थीं। वहीं भाजपा महज 15 सीटों में ही सिमट गई थी। इस साल के अंत तक यानी की नवंबर-दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं।

बीजेपी ने लखनलाल देवांगन को छत्तीसगढ़ की

कोरबा विधानसभा सीट से और पाटन से सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। सीएम बघेल विधानसभा में पाटन सीट पर दावेदारी पेश करते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिन्हें पार्टी अपने लिए कमजोर मान रही है। बीजेपी ने यह प्रयोग इसलिए किया है, जिससे की पार्टी उम्मीदवारों को कमजोर सीटों पर संपर्क और प्रचार करने का ज्यादा मौका मिल सके। पार्टी दावा कर रही है कि आम आदमी से करीब 6 लाख कार्यकर्ता जुड़े हैं। आप ने हर ग्राम पंचायत पर संगठन को मजबूती से खड़ा कर लिया है। चुनाव से लगातार ठीक पहले कई बड़े नेता पार्टी से जुड़ रहे हैं। बता दें कि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 1 लाख 25 हजार वोट मिले थे। हालांकि यह आंकड़ा एक प्रतिशत से भी कम था। राजनीतिकारों का मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है।

राजनांदगांव की जनता इस बार किसे देगी मौका

छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए अभी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि 15 साल तक सत्ता में केंद्र बिंदू रही राजनांदगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा है। विधायक डॉ. रमन सिंह लगातार तीन बार राजनांदगांव से मुख?यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव को अहम सीट माना गया है। राजनांदगांव सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 किस पार्टी के पक्ष में जाता है। यह जनता तय करेगी। लेकिन अगर इस क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो साल 2018 में यहां पर मतदाताओं की संख्या 1,97,661 है, जो साल 2023 में अपना नेता चुनेंगे। राजनांदगांव विधानसभा सीट के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर हो गई। यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। सड़कों की मरम्मत ना होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में खासी परेशानी का समाना करना पड़ता है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों ने बीएनसी मिल के अलावा नया उद्योग लाने की मांग की है। जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस सीट के ग्रामीणजन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार कराने की भी मांग कर रहे हैं। जिससे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और सूखे की समस्या से किसानों को निजात मिल सके।

राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं होने से क्षेत्र की जनता में खासी नाराजगी है। इस क्षेत्र की जनता चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। राजनांदगांव से अलग हुए दो जिलों के बाद अब संभाग को बनाने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौक को नया जिला बनाया गया था। भाजपा का गढ़ कही जाने वाली राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस कब्जा करने के लिए काफी प्रयास कर रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बलौदाबाजार (छ.ग.)
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

ऑनलाईन निविदाएँ प्रपत्र-ए में प्रतिशत दर पर एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के निम्नलिखित विकासखण्ड के ग्रामों में नलकूप खनन कार्य की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा सूचना क्र./ दिनांक	सिस्टम क्र.	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
84/15.09.2023	148058	57.24
85/15.09.2023	148116	57.24
86/15.09.2023	148139	66.78
87/15.09.2023	148147	66.78
88/15.09.2023	148152	52.47
90/15.09.2023	148131	50.32
91/15.09.2023	148149	40.80
92/15.09.2023	148154	38.08

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति,निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबपोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in मे दिनांक 11.10.2023 तक देखी जा सकती है एवं निविदा डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

जी-05983/6

जातीय गणना से अति पिछड़ा वर्ग को कैसे मिलेगा हक

डी श्याम बाबू

बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस सर्वे के चलते देश के सामाजिक माहौल में एक बार फिर हलचल होगी। मांग उठेगी कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना में लोगों से जाति भी पूछी जाए। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। साथ ही, जस्टिस रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठेगी। यह रिपोर्ट हाल में सरकार के पास जमा की गई थी। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सेंट्रल लिस्ट की 2600 जातियों की सब-कैटिगरी बनाने के मुद्दे पर विचार किया था। दरअसल, जाति का जिन्न बोतल के अंदर कभी था ही नहीं। लिहाजा इस रोने-धोने का कोई मतलब नहीं बनता कि जातिवार गिनती करने से समाज बंट जाएगा। इससे कहीं ज्यादा वजनदार दलील यह है कि सैकड़ों जातियों को आरक्षण के दायरे में लाना प्रशासनिक रूप से बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन यह दलील भी जातिगत आधार पर ज्यादा आरक्षण देने की मांग पर भारी नहीं पड़ सकेगी। जाति की राजनीति को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, इसके पीछे वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा जोर लगाया था। उन्हें इसका चुनावी लाभ मिलेगा। नीतीश ही थे, जिन्होंने 25 साल पहले भारतीय राजनीति को मंडल और कमंडलवादी ताकतों की जोर-आजमाइश में बदल दिया। तब बहुसंख्यक ओबीसी को मंडल कमिशन के जरिए आरक्षण मिला। वहीं, अल्पसंख्यक अपर कास्ट के लोग दबदबे के लिए धर्म यानी कमंडल का सहारा लेते हैं। नीतीश का मानना है कि इन दोनों में टकराव है। इस तस्वीर से नीतीश को बड़ा चुनावी फायदा मिला है कि शोषित बहुसंख्यक लोग शोषण करने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक वाजिब जंग लड़ रहे हैं। यह और बात है कि नीतीश ने एक बैले डांसर जैसा कौशल दिखाया है और वह मंडल और कमंडलवादी खेमों के बीच आते-जाते रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा से हाथ मिलाकर वह एक बार फिर कमंडल खेमे में चले जाएं। जहां तक भाजपा की बात है, तो 2014 से ऐसा लग रहा है कि उसने मंडल को कमंडल में मिला दिया है। ऐसा उसने हिंदुओं की एकता पर जोर देकर किया है। भाजपा की चुनावी कामयाबी में बड़ा योगदान मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज (एमबीसी) के समर्थन का रहा है। उनकी शिकायतें वाजिब थीं। भाजपा ने उनको आवाज देकर फायदा उठाया। अब भाजपा से कहा जा रहा है कि वह भी इन वर्गों को फायदा पहुंचाए। पेच यह है कि अगर अपने एमबीसी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ओबीसी ने भी एक तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया, तो अगड़ी जातियों वाले उसके समर्थक नाराज हो जाएंगे। फिलहाल बीजेपी कास्ट सेंसस का और इस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विरोध कर रही है। इसके पीछे मजबूत प्रशासनिक वजहें हैं, लेकिन इस विरोध के चलते खतरा यह है कि एमबीसी वोट बीजेपी के हाथ से निकल सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर यह राजनीतिक मामला भर नहीं है। बिहार के कास्ट सर्वे से सामने आए आंकड़े हैरतअंगेज हैं। बिहार की कुल आबादी में लगभग साढ़े 84 प्रतिशत लोग ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी से हैं। अगड़ी जातियों के लोग लगभग साढ़े 15 प्रतिशत ही हैं। करीब 18 प्रतिशत की पूरी मुस्लिम आबादी को ओबीसी/एमबीसी में शामिल कर लिया गया है। अगर यह मान लिया जाए कि इसी तरह के आंकड़े पूरे देश में भी आ सकते हैं और इसमें 10 प्रतिशत तक की गलती होने की आशंका को भी शामिल कर लिया जाए, तो तस्वीर में तीन बड़ी चीजें दिखती हैं। कुल आबादी के एक चौथाई से भी कम जनसंख्या वाले समूह नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों की तीन चौथाई तक सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। कुछ चीजें साफ तौर पर जातियों के ऊंचे या नीचे होने से जुड़ी हुई हैं।

भ्रष्टाचार की सफाई करने में जुटे हैं मोदी

ललित गर्ग

देश में स्वच्छता अभियान से ज्यादा जरूरी हो गया राजनीतिक स्वच्छता अभियान। क्योंकि आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने के लिये राजनीति का शुद्धिकरण यानी अपराध एवं भ्रष्टाचारमुक्त होना अपेक्षित है। आज कौन-सी पार्टी है जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन कर रही है? शोचनीय बात यह है कि अब भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता को पोषित करने वाले एवं देशविरोधी राजनीति के दोषी शर्मसार भी नहीं होते। इस तरह का राजनीतिक चरित्र देश के समक्ष गम्भीर समस्या बन चुका है। राजनीति की बन चुकी मानसिकता और भ्रष्ट आचरण ने पूरे लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया है। स्वहित और स्वयं की प्रशंसा में ही लोकहित है, यह सोच हमारी राजनीति में घर कर चुकी है। यह रोग राजनीति को इस तरह जकड़ रहा है कि हर राजनेता लोक के बजाए स्वयं के लिए सब कुछ कर रहा है। अधिकतर राजनीतिज्ञों का मकसद बस किसी तरह चुनाव जीतना और सत्ता में जाना हो गया है। चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और सत्ता में आने पर पैसा बनाने के सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ वर्ष पहले स्वच्छता अभियान छेड़ा, जिसका व्यापक असर हुआ। अब देश में दूषित होती राजनीति में स्वच्छता अभियान शुरू करने की पहल करने की अपेक्षा है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा। ऐसे दौर में राजनीति में सुधार की कोरी बातें ही नहीं बल्कि संकल्पित होने का वक्त आ गया है। यह वक्त देखा जाए तो चुनाव सुधार एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों को बल देने का बिगुल बजाने का है। चुनाव में अच्छे एवं ईमानदार, लोग चुन कर आएं इसके लिए राजनीति में अपराधियों का प्रवेश तो रोकना ही होगा, वंशवाद, जातिवाद, धनबल व बाहुबल जैसी राजनीति में घुस आई गंदगी को साफ करने के लिए 'जागरूकता की झाड़ू' को उठाना ही होगा। अभी तो आम धारणा यही बनती जा रही है कि ईमानदारी के बलबूते चुनाव जीतना आसान नहीं है। लेकिन आगामी चुनावों में इस धारणा को बदल देना है। चुनाव सुधारों को लेकर उच्चतम न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक की सिफारिशें एवं सुझाव हर

बार हवा होते रहे हैं। उन पर अमल करने की परवाह किसी को नहीं होती। ठीक इसी तरह राजनीति के शुद्धिकरण का संकल्प भी हर चुनाव में खारिज होता रहा है, लेकिन कब तक? प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में नैतिक एवं ईमानदार चेहरा को प्रोत्साहन दिया है। ऐसा करके उन्होंने यह भी जता दिया कि राजनीति की चली आ रही परिभाषाएं अब बदलने लगी हैं। अब मोदी के नाम पर उन राज्यों में चुनाव जीतने के कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जहां चुनाव जीतना किन्हीं खास धनबल, बाहुबल एवं अपराधिक तत्वों के नाम लिखे हुए थे।

बात लोकसभा चुनाव की नहीं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों की है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव इतने सफल क्यों एवं कैसे हो रहे हैं? पार्टी के कद्दावर नेता, जिनके बिना राज्य में चुनाव जीतना असंभव माना जाता रहा है, उन नेताओं के नाम की बजाय मोदी के नाम पर वोट मांगने की परम्परा मजबूत एवं सफल होती जा रही है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक है विकास का, मूल्यों का, जन समस्याओं के समाधान का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई। दूसरे कार्यकाल के बाद विकास, शांति एवं सौहार्द का प्रतीक बन गए। गुजरात मॉडल का प्रचार इतना जबर्दस्त रहा कि अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। बिहार-यूपी जैसे सुदूर क्षेत्रों के लोग भी गुजरात मॉडल की बात करने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रांड मोदी और भी मजबूत हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मोदी अपराजेय दिखने लगे। 2024 के चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने यही सवाल खड़ा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला नेता कौन होगा? इंडिया के सामने नेता घोषित करने की दोहरी चुनौती है। अगर चुनाव से पहले इंडिया का नेता चुन लिया गया, तो उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से होगी। अगर नहीं चुना गया तो विपक्ष बिखरा ही दिखाई देगा।

नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आलोचना की परवाह किए बगैर कई ऐस देशहित के बड़े फैसले लिए, जिनसे न सिर्फ विपक्ष बल्कि भारत की जनता भी चौंक गई। नोटबंदी, उरी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान समर्थित कश्मीर में एयर स्ट्राइक की विपक्ष ने आलोचना की, कश्मीर में राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इन निर्णयों से कश्मीर के नेता बौखला गये, भारी विरोध किया, मगर नरेंद्र मोदी ने इस पर कभी अफसोस नहीं जताया। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के फैसला भी विरोधियों के निशाने पर रहा। सीएए को लेकर भी काफी हो-हल्ला हो चुका है। 2024 के चुनाव में जाने से पहले नरेंद्र मोदी चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। 18 सितंबर 2023 से संसद का विशेष सत्र में नारी वन्दन विधेयक पारित किया। वैसे चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना तय है।

मोदी की साफ-सुथरी छवि एवं भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति का ही परिणाम है कि विपक्ष की अनेक कोशिशों के बावजूद वे उनके खिलाफ कोई एक भी मुद्दा नहीं खोज पाये। केंद्र की मोदी सरकार ने राजनीति में बड़े बदलाव भ्रष्टाचार और करप्शन के मुद्दे पर किए हैं। 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उछाला था। बोफोर्स से जुड़े कांग्रेस नेताओं के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता। नरसिंह राव की सरकार भी घोटालों के घिरी थी, जिसका फायदा बीजेपी समेत विपक्ष को मिला था। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार कोयला घोटाले, 2जी और कॉमनवेल्थ घोटाले की चर्चा के बीच चुनाव में गई थी, नतीजा कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस ने भी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को घोटाले पर घेरने की कोशिश की, मगर ब्रांड मोदी के सामने उसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाई। 2019 में कांग्रेस ने राफेल में करप्शन का मुद्दा उठाया। नोटबंदी में करप्शन के आरोप लगाए। अडानी और अंबानी के मुद्दे को चुनाव में उठाया, मगर मोदी मैजिक के सामने सारे वार फेल हो गए। 2024 से पहले कांग्रेस फिर अडानी और अंबानी के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे उलट इंडिया के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है।

देश में आशावाद और सकारात्मकता का माहौल है, लोग जी20, चंद्रयान और अर्थव्यवस्था की सफलता का उत्सव मना रहा है, 2024 में एक बड़ी जीत के लिए आश्वस्त दिखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने की ठानी है तो यह समय आम मतदाता के जागरूक एवं सर्तक होने का भी है। राजनीति में सुधार चाहने वालों के लिए यह घर बैठने का समय नहीं है। राजनीति में नैतिकता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव सुधारों की कोरी बातें ही नहीं बल्कि उन पर अमल लाने की भी जरूरत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है कि वे ठोक-बजाकर उम्मीदवारों का चयन करें। चिंता इस बात की है कि जनता ही दागियों को वोट देकर सत्ता में लाती है। इसलिए प्रमुखत: राजनीति में स्वच्छता के लिए कदम उसे भी बढ़ाने होंगे। वर्ना मोदी का करिश्मा एवं जादू तो अपना असर दिखायेगा ही, क्योंकि उनके पास सत्य एवं नैतिकता का बल है। मोदी ने ही देश पर लगे गरीब होने के दंश को हटाने की सार्थक पहल की है, उन्हीं के शब्दों में लंबे वक्त तक, भारत की पहचान एक अरब से अधिक भूखे पेटों वाले देश के रूप में रही है, लेकिन अब, भारत को एक अरब से अधिक उम्मीदों से भरे दिमाग, दो अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में मोदी के नाम पर मांगे जा रहे वोट उन्हें ऐतिहासिक जीत दे तो कोई आश्चर्य नहीं है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

इस नश्वर जगत् में उत्पन्न हुए उन्हीं प्राणियों का जीवन उत्कृष्ट है, जिन्हें पुन: आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इससे भिन्न तो जरावस्था को प्राप्त गधे के सदृश हैं, जो कि अशक्त होते हुए भी भार ढोने के लिए विवश हैं। ज्ञानवान् मनुष्य के लिए शास्त्र, भार ढोने के सदृश है। राग-द्वेष में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भारस्वरूप है, अशान्त मनुष्य का मन तो स्वयं में ही भारस्वरूप होता है तथा जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए यह शरीर भी बोझा ढोने के सदृश ही है।

अहंकार ही समस्त विपत्तियों के आगमन का हेतु है। इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और तरह-तरह की इच्छा-आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण मनुष्य का अहंकार से बढ़कर और कोई भी शत्रु नहीं है। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने चराचर रूप जिन-जिन भोगों का उपभोग किया है, वे सभी मिथ्या, भ्रमरूप थे। अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता है। वस्तु तो मात्र अहंकार शून्यता ही है। यह मन व्यर्थ ही परेशान होकर यत्र-तत्र दौड़ता रहता है। व्यर्थ ही दूर-दूर तक भ्रमण करता रहता है। इसका स्वभाव गाँव में इधर-उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह है। मैं भी तृष्णारूपी कुतिया के पीछे-पीछे कुत्ते की भाँति भटकता हुआ इस प्रकार क्रूर मन के वशीभूत होकर जड़वत् हो गया था। हे ब्रह्मन्! अब मैं उसके प्रभाव से पूर्णरूपेण मुक्त हो गया हूँ। हे ब्रह्मन्! चित्त को नियंत्रित करना, समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकने से भी कठिन है और अग्नि के भक्षण से भी कठिन है। यह चित्त बाह्य एवं अन्त:करण में विषय भोगों को ग्रहण करने वाला है, उसके आधार पर ही जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से युक्त संसार की स्थिति निर्भर है। चित्त के नष्ट होने पर यह जगत् नष्ट हो जाता है। अत: प्रयासपूर्वक चित्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए। वायु का लपेटना, आकाश को खण्ड-खण्ड करना एवं जल की लहरों का गुन्धन भले ही सम्भव हो जाए, किन्तु जीवन में आस्था एवं विश्वास रखना सम्भव नहीं हो पाता। जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु को (सम्यक् रूप से) प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण शोक न करना पड़े और जिसमें परम शान्ति की उपलब्धि हो जाए, वही तो वास्तविक जीवन कहलाता है। यों तो वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी जीवन धारण किये रहते हैं; किन्तु यथार्थ में वही जीवित है, जिसका मन निरन्तर आत्मचिन्तन में लीन रहता है। इस नश्वर जगत् में उत्पन्न हुए उन्हीं प्राणियों का जीवन उत्कृष्ट है, जिन्हें पुन: आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इससे भिन्न तो जरावस्था को प्राप्त गधे के सदृश हैं, जो कि अशक्त होते हुए भी भार ढोने के लिए विवश हैं। ज्ञानवान् मनुष्य के लिए शास्त्र, भार ढोने के सदृश है। राग-द्वेष में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भारस्वरूप है, अशान्त मनुष्य का मन तो स्वयं में ही भारस्वरूप होता है तथा जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए यह शरीर भी बोझा ढोने के सदृश ही है।

क्रमश: ...

दान देकर लौटाया आजीविका का कर्ज

विष्णु कछावा

मैं मूलत: मध्य प्रदेश के नीमच जिले से हूँ, लेकिन केरल का कन्नूर मेरा दूसरा घर है। मेरे एक बड़े भाई अध्यापक हैं और बाकी के हम सभी भाई कंबल का व्यापार करते हैं। केरल ने मुझे रहने के लिए घर दिया है, परिवार को चलाने के लिए आजीविका दी है आज और सबसे बड़ी बात कि मुझे इस राज्य में एक बेहतरीन जलवायु मिली है। किसी जगह ने आपको इतनी चीजें दी हो और जब वह संकट में हो, तो आपका फर्ज बनता हैं कि आप भी उसे कुछ लौटाएँ।

मेरी उम्र सोलह साल थी, जब मैं केरल आ गया था। फिलहाल मैं यहाँ अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता हूँ। पिछले बारह वर्षों से मैं कन्नूर जिले के इरिटी इलाके में काम कर रहा हूँ। मैं यहा घूम-घूमकर कंबल, पायदान और दूसरी तरह के कपड़े बेचता हूँ। मैं साझेदारों के साथ मिलकर उत्तर भारत से कंबल मँगाकर यहाँ व्यवसाय करता हूँ। यहाँ बिताए लंबे वक्त के दौरान मैंने कभी यहाँ के लोगों को उतना बेबस नहीं पाया, जितना कि इन दिना आई भीषण बाढ़ के दौरान देखा है।

मैं जिन जगहों में जाकर कंबल बेचता हूँ, उनमें इरिटी तालुक का दफ्तर भी शामिल है। दस दिन पहले की बात है। दर्जनों कंबलों के ढेर के साथ मैं

इरिटी तालुक दफ्तर पहुँचा, तो वहाँ के अधिकारियों ने खराब मौसम और भूस्खनल की आशंकाओं को लेकर मुझे चेताया। एक अधिकारी ने मुझे भारी बारिश की वजह से दूर-दराज के गाँवों में न जाने की हिदायत दी।

दरअसल सही कीमत और साफ व्यापार के चलते अधिकारी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को मेरे सामान पर भरोसा होता है। उनकी व्यक्तिगत सलाह मेरे भरोसे का प्रतिफल थी। लेकिन मैं तो उन दिन कंबल बेचने निकला ही नहीं था। मैंने उन अधिकारियों से कहा कि मैं ये कंबल दान करने के लिए लाया हूँ। चूंकि हर जरूरतमंद तक पहुँच पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके कंबलों को उचित व्यक्तियों को बाँटा जा सकता है। मैंने अपनी बात कही, मगर अधिकारियों को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि मैं ये सारे कंबल दान कर दूँगा तो फिर घर कैसे चलाऊँगा। मगर मेरी प्रतिबद्धता देखते हुए अधिकारी मुझे एक राहत शिविर में ले गए। संयोग ही था कि शिविर में जिलाधिकारी भी पहुँचे हुए थे। मैंने सारे कंबल उन्हीं को सुपुर्द कर दिए।

मेरे लिए यह एक ऐसा मौका था, जब मैं उस भूमि को कुछ वापस कर रहा था, जिसने मुझे जीवन दिया है। हालांकि यह भी सच है कि किसी उत्तर भारतीय श्रमिक का दक्षिणी राज्यों में काम कर पाना इतना आसान भी नहीं है, जिसमें भाषा एक बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन यदि स्थानीय भाषा सीख ली जाए, तो मूल निवासियों और उत्तर भारत के %भैया% के बीच की दूरी बहुत तेजी से घटती है।

मैं साल में दो-तीन दफे हरियाणा से माल मँगाता हूँ। कमाई का बड़ा हिस्सा नीमच में रह रहे अपने परिवार के लिए भेज देता हूँ। काम की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी, जिसे मैं दोबारा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत मैंने स्नातक में प्रवेश लिया है। मैं अब केरल में ही रहना चाहता । यही के सुख-दुख का हिस्सा बनना चाहता हूँ और यह भी ख्वाहिश हैं कि इसी धरती की संस्कृति में घुल-मिल जाऊँ।

जस्टिन ट्रूडो के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त रुख

हरीश गुप्ता

ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कनाडा के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है और भविष्य में इस पर पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है। जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने आरोप को सार्वजनिक करते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में 'भारत सरकार के एजेंट' शामिल थे, तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में कहा कि ये आरोप भारत की नीति के अनुरूप नहीं थे और उन्होंने आरोपों को 'बेतुका और प्रेरित' बताया। उन्होंने ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के खिलाफ अपने आरोप के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है।

हालांकि, वाशिंगटन ने कहा कि यह आई 5 देशों के गठबंधन (अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के बीच साझा खुफिया जानकारी है और भारत को इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं हैं। भारत सरकार ने भारत में मौजूद 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने कनाडा और वाशिंगटन को दृढ़ता से बताया कि कनाडा का 'आतंकवादियों, चरमपंथियों और भारत के खिलाफ हिंसा की खुलेआम वकालत करने वाले लोगों के प्रति उदार रवैया' है और वह उन्हें शरण दे रहा है।

सवाल यह है कि कनाडा भारत के खिलाफ सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? दरअसल

कनाडा किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि वियना समझौते के तहत, किसी भी देश द्वारा राजनयिकों की जासूसी नहीं की जा सकती है और उन्हें ऐसी किसी भी कार्रवाई से छूट हासिल है। यदि कनाडा आधिकारिक तौर पर भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करता है, तो यह स्थापित हो जाएगा कि कनाडा या अमेरिका ने कनाडा में काम करने वाले राजनयिकों की अवैध रूप से जासूसी की थी। इस तरह के खुलासे के निज्जर हत्याकांड से भी ज्यादा दूरगामी परिणाम होंगे। शायद ट्रूडो को इस बात का अहसास नहीं था कि वह एक अलग भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के लिए कनाडा एक ऐसा देश है, जहां 'भारत के खिलाफ संगठित अपराध के तार मानव तस्करी, अलगाववाद, हिंसा, जबरन वसूली और आतंकवाद से जुड़े हैं।'

पीएम मोदी ने कनाडाई पीएम से दृढ़ता से कहा कि वे वहां स्वतंत्र रूप से सक्रिय भारत विरोधी आतंकवादियों की सूची पर कार्रवाई करें जो उन्होंने 2018 में उन्हें सौंपी थी। कथित तौर पर मोदी ट्रूडो के प्रति सख्त रहे जब वे दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे लेकिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया और मोदी ने अपनी शैली में काम करने का फैसला किया। यह याद रखना चाहिए कि मोदी ने अमेरिका से दृढ़तापूर्वक कहा था कि भारत उसके लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद रूसी तेल का आयात जारी रखेगा। मोदी ने वाशिंगटन से कहा कि रूस से तेल आयात करना उसके 'तेल सुरक्षा और राष्ट्रीय हित' का हिस्सा है। अमेरिका को इसे नजरंदाज करना पड़ा।

पीएम मोदी ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया था जब उन्होंने 2019 में बालाकोट में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय बलों को पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति दी। भारत की घोषित नीति थी कि वह दुश्मन पर हमला करने के लिए कभी भी सीमा पार नहीं करेगा और सिर्फ खुद का बचाव करेगा। लेकिन, बालाकोट ने सब कुछ बदल दिया और मोदी ने पाकिस्तान के अंदर सीधा हमला करने का फैसला किया। दुनिया भर में हमारी शीर्ष खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, इस पर नजर रखने वालों का कहना है कि मोदी के आक्रामक रवैये के लिए काफी हद तक अजित डोभाल जिम्मेदार हैं, जो पिछले दस सालों से पीएमओ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) हैं। डोभाल इंदिरा गांधी के समय से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ हैं। यह वही थे जिन्होंने 2005 में दुबई में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए एक ज्ञात आतंकवादी गिरोह का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे और उसी साल जनवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन उन्होंने भारतीय एजेंसियों को उनके कार्यों में सहायता देना जारी रखा। उल्लेखनीय है कि तब सरकार का नेतृत्व डॉ. मनमोहन सिंह कर रहे थे। यह अलग बात है कि तब मुंबई पुलिस की बेवकूफी के कारण ऑपरेशन विफल हुआ था। डॉ. सिंह के एनएसए एम.के. नारायणन 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास परिसर में हुए विस्फोटों के बाद, जिसमें रक्षा सहकारी रवि मेहता और विदेश सेवा अधिकारी वी. वेंकटेश्वर राव सहित 58 लोग मारे गए थे, जांच में शामिल हो गए। नारायणन ने सभी पुलिस प्रमुखों से कहा, 'बातचीत के दिन खत्म हो गए हैं. यह कार्रवाई का समय है।' डोभाल मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि 'पाकिस्तान से उसकी भाषा में बात करें' और 'आक्रामक रक्षा' आज का सिद्धांत होना चाहिए। यदि हाल के दिनों में पाकिस्तान, इटली और अन्य जगहों पर एक दर्जन से अधिक कट्टर आतंकवादियों का सफाया किया गया है, तो यह याद रखना चाहिए कि भारत ने मोदी के शासन के अंतर्गत अपनी नीति बदल दी है। भारत ने पश्चिमी दुनिया को बता दिया है, 'अगर हम पैसा कमाने के लिए आपको अपना बाजार दे रहे हैं, तो इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी और कनाडा को आतंक के खिलाफ कदम उठाना ही होगा।' इस नए युग के एक गुमनाम नायक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल हैं, जो 1984 के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो जून 2023 तक चार साल तक इस पद पर रहे। भारत के बाहर के अधिकांश गुप्त ऑपरेशन के लिए उनके नेतृत्व में रॉ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नि:संदेह, डोभाल इन एजेंसियों में क्या हो रहा है, उस पर अपनी कड़ी नजर रख रहे थे।

हिन्द स्वराज्य

गोला-बारूद (भाग-5)

गतांक से आगे...

आप खिड़की-दरवाजे खुले कर देते हैं। आप अपनी सोने की जगह बदल देते हैं। आप अपनी चीजें झट ले जायी जा सकें इस तरह रख देते हैं। चोर आता है। वह घबराता है। यह सब उसे नया ही मालूम होता है। माल तो वह ले जाता है, लेकिन उसका मन चक्कर में पड़ जाता है। वह गाँव में जाँच-पड़ताल करता है। आपकी दया के बारे में उसको मालूम होता है। वह पछताता है और आपसे माफी माँगता है। आपकी चीजें वापस ले आता है। वह चोरी का धंधा छोड़ देता है। आपका सेवक बन जाता है। आप उसे काम-धंधे से लगा देते हैं। यह दूसरा साधन है। आप देखते हैं कि अलग-अलग साधनों के अलग-अलग नतीजे आते हैं। सब चोर ऐसा ही बरताव करेंगे या सब में आपका-सा दयाभाव होगा, ऐसा मैं इससे साबित नहीं करना चाहता। लेकिन यही दिखाना चाहता हूँ कि अच्छे नतीजे लाने के लिए अच्छे ही साधन चाहिए। और अगर सब नहीं तो ज्यादातर मामलों में हथियार बल से दया बल ज्यादा ताकतवर साबित होता है। हथियार में हानि है, दया में कभी नहीं। अब अरजी की बात है। जिसके पीछे बल नहीं है वह अरजी निकासी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी स्व. न्यायमूर्ति रानडे कहते थे कि अरजी लोगों को तालीम देने का एक साधन है। उससे लोगों को अपनी स्थिति का भान कराया जा सकता है और राजकर्ता को चेतावनी दी जा सकती है। यो सोचें तो अरजी निकम्मी चीज नहीं है। बराबरी का आदमी अरजी करेगा तो वह उसकी नम्रता की निशानी मानी जायेगी। गुलाम अरजी करेगा तो वह उसकी गुलामी की निशानी होगी। जिस अरजी के पीछे बल है वह बराबरी के आदमी की अरजी है; और वह अपनी माँग अरजी के रूप में रखता है, यह उसकी खानदानियत को बताता है। अरजी के पीछे दो तरह के बल होते हैं। एक है- अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे। यह गोला-बारूद का बल है। इसका बुरा नतीजा हम देख चुके। दूसरा बल यह है-अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके अरजदार नहीं रहेंगे। हम अरजदार होंगे तो आप बादशाह बने रहेंगे।

क्रमश: ...

मप्र में भी महत्वपूर्ण हुई ओबीसी वोट की राजनीति

सिद्धार्थ शंकर गौतम

इतिहास स्वयं को दोहराता है किंतु इस बार उल्टा हो रहा है। जातियों की जकड़न से हिन्दू समाज को निकालने की मंशा से हिंदुत्ववादी राजनीति की शुरुआत हुई और अब हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार को समाप्त कर हिन्दू समाज को पुन: जातियों के फेर में बांटने की साजिश रची जा रही है। %जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी% का राग भी वे नेता अलापने में लगे हैं जिन्होंने हिस्सेदारी न होते हुए भी राजनीति में पूरी भागीदारी से अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है।

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बोलते हुए कहा, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। यह लोग कानून बनाते हैं। कितना पैसा कहां जाना है, यह तय करते हैं। बीजेपी की दस साल से सरकार है। ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50 प्रतिशत है। 90 अफसरों में सिर्फ तीन अफसर ओबीसी के हैं। यह देश की सच्चाई है।

ओबीसी राजनीति को हवा देते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान का बजट लाखों-करोड़ों का है। ओबीसी अफसर की भागीदारी बजट में कितनी है? यह कितने रुपये पर निर्णय लेते हैं? तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपये का बजट है। किसी को पता ही नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में पांच प्रतिशत की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। सही में मोदी ओबीसी के लिए काम करते हैं तो 90 अफसरों में उनकी संख्या तीन क्यों है? ओबीसी की जेब से पैसा चोरी हो रहा है। राहुल गांधी के भाषण के अगले दिन ही बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ें

सार्वजनिक कर देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। उबाल तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आया है जहां अब ओबीसी केन्द्रित चुनाव होना तय है।

2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान %माई का लाल% ने 15 वर्ष बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। गौरतलब है कि 2018 में आरक्षण विवाद के चलते अनुसूचित जातियों और सवर्ण जातियों का बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज हो गया था। हालांकि डेढ़ वर्ष पश्चात ही मध्य प्रदेश में पुन: भाजपा की सरकार बनी किन्तु उसके बाद सरकार ने जातीय समीकरण साध लिए। मध्य प्रदेश में उत्तर भारतीय राज्यों की भांति जातिवाद राजनीति में कम ही घुला था किन्तु 2023 के विधानसभा चुनाव अब इससे अछूते नहीं रहे हैं। बीते एक वर्ष में भाजपा और कांग्रेस ने जमकर जातीय सम्मेलन किए हैं। यहां तक कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने जातियों के हिसाब से उनके महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश की चुनावी घोषणा भी कर दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी है जबकि प्रदेश की 50.09 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है। 230 सीटों वाली विधानसभा में कुल 82 सीटें (47 अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति) इन वर्गों के लिए आरक्षित हैं। विंध्य क्षेत्र सवर्ण बहुल है तो चंबल पिछड़ी जातियों का गढ़ है। मालवा-निमाड़ वनवासी बहुल क्षेत्र है तो मध्य भारत और महाकोशल संभाग में ओबीसी अधिक हैं। ऐसे में हर क्षेत्र के हिसाब से राजनीतिक दलों को अपनी गोटियां फिट करना पड़ रही हैं। प्रदेश की 20-25 अनारक्षित विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक दल जीतने के लिए सवर्ण के बजाए ओबीसी प्रत्याशी उतारते रहे हैं। इस बार ओबीसी कार्ड के चलते ऐसी सीटों पर और अधिक ओबीसी प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन गई है।

प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता स्व. पंडित रविशंकर शुक्ल (1952-56) से लेकर प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता स्व. श्यामा चरण शुक्ल (1969-72,1975-77) तक प्रदेश की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द-गिर्द घूमती रही जिसका तिलिस्म स्व. अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में टूटा और प्रदेश में राजपूत समुदाय की राजनीति हावी होने लगी जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर हवा दी। 2003 में भाजपा नेतृत्व ने ओबीसी में आने वाली लोधी जाति की उमा भारती को कमान सौंपी और उसके बाद बाबूलाल गौर (यादव) तथा शिवराज सिंह चौहान (किरार) के चलते उसे पिछड़ी जातियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। वर्तमान में ओबीसी वर्ग से भाजपा के 40 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 19 विधायक ओबीसी समुदाय से हैं।

हालांकि मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना के संभावित परिणाम और आरक्षण को लेकर अभी उतनी चर्चा नहीं है जिसके चलते यह वर्ग भाजपा से जुड़ा हुआ है किन्तु कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग करके इस वर्ग को भाजपा से दूर करने का दंभ भर दिया है जिससे अब तक एकतरफा नजर आ रहा विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर का हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 1984 में लागू हुआ था जो 14 प्रतिशत था। 08 मार्च, 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में एक्ट बनाकर आरक्षण का दायरा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसका फैसला भाजपा-कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यह कह चुका है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 36 प्रतिशत है वहां ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण समझ से परे है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती अत: मध्य प्रदेश में भी आरक्षण का मामला उलझा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने की जुगत से जातिगत जनगणना की मांग उठाना, प्रदेश में जातीय जहर बोने जैसा है जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट पर जारी एक सूची के अनुसार मुस्लिम समुदाय में शामिल 38 जातियां भी ओबीसी में शामिल की गई हैं जिसमें रंगरेज, भिश्ती, हेला, धोबी, मेवाती, मनिहार, कसाई, मिरासी, बढ़ई, हज्जाम, हम्माल शामिल हैं। इस मामले में भी तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है और किसे अपनी सवारी करवाता है।

जातिगत जनगणना के दांव से कैसे बचेगी भाजपा

अमित शर्मा

बिहार सरकार के द्वारा जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करने से एक सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस के खुलकर इसके पक्ष में आ जाने से यह भी स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष इसे अपना प्रमुख मुद्दा बनाकर 2024 में मोदी सरकार को चुनौती देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा विपक्ष के इस संभावित हमले से पूरी तरह अनजान थी। भाजपा नेताओं की मानें तो उन्हें इस संभावित हमले की पूरी जानकारी थी। पार्टी ने इससे बचने का पूरा प्लान भी तैयार कर रखा है। उसने पहले ही ओबीसी आयोग बनाने, मेडिकल और शिक्षा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने और क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने जैसे काम कर रखे हैं। इसके सहारे पार्टी को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना के दांव से उसे कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चल रही बहस के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय को भागीदारी देने का मुद्दा उठाया था। इस पर अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 29 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। भाजपा के 85 सांसद, 27 फीसदी विधायक और 40 फीसदी एमएलसी ओबीसी समुदाय से ही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही ओबीसी समुदाय को भागीदारी देने में आगे रही है। ऐसे में विपक्ष को उन पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि स्वयं उसने (विपक्ष ने) ओबीसी समुदाय को पर्याप्त भागीदारी नहीं दी है। भाजपा ओबीसी समुदाय की इस राजनीति को पहले ही उस स्तर पर ले जा चुकी है, जहां विपक्ष का कोई दल अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा ने ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी राह में कानूनी अड़चनें खड़ी कर इसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक चली लड़ाई में अंतत: योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत हुई और पंचायत चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जा सका। भाजपा के ओबीसी मोर्चे में काम कर रहे ओबीसी समुदाय के नेता प्रमोद ने अमर उजाला से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। यही कारण है कि अब पूरे देश का ओबीसी समुदाय मोदी सरकार के साथ खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। इससे जातिगत राजनीति करने वाले कुछ दलों की जमीन खिसक रही है, जिसको बचाने के लिए नीतीश-लालू जैसे नेता जातिगत आरक्षण का दांव खेल रहे हैं। लेकिन अपने कामों के दम पर भाजपा को यकीन है कि वह ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहेगी और उसे जातिगत आरक्षण से नुकसान नहीं होगा। सीएसडीएस के प्रो. संजय कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के जातिगत आंकड़ों में बहुत कुछ नया नहीं है। जातिगत हिस्सेदारी लगभग वही है जिसका पहले से अनुमान लगाया जाता रहा है। इसमें थोड़ा-बहुत ही बदलाव हुआ है, जिससे समाज में बड़ा परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है। लेकिन यदि इन्हीं आंकड़ों में जातिगत समूहों की आर्थिक स्थिति का आकलन पेश किया गया होता, तो यह लोगों में ज्यादा संवेदनशीलता पैदा करता। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इन आंकड़ों के साथ सामने आए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, केवल इन आंकड़ों से सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि क्योंकि उसने ओबीसी मुद्दे पर पहले ही बहुत काम किया है। लेकिन जातिगत आंकड़ों से असली परेशानी आरक्षण बढ़ाने को लेकर आ सकती है। ओबीसी समुदाय अब अपनी बढ़ी हिस्सेदारी से ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50 फीसदी या इससे ज्यादा करने की मांग कर सकता है। लेकिन कानूनी बाधाओं के चलते इसे कर पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए संविधान में बदलाव की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो किसी भी तरह आसान नहीं होगी। वहीं, यदि सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, तो उसके दूसरे मतदाता वर्ग भी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में विपक्ष के दावों के कारण भाजपा के सामने आरक्षण के मोर्चे पर परेशानी देखने को मिल सकती है। आरक्षण का मुद्दा देश की राजनीति में पहले भी अपना असर दिखा चुकी है। इससे निपटना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है।

मप्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान

अनन्या मिश्रा

मप्र विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कांटे से कांटा निकालने की रणनीति तैयार की है। बता दें कि राज्य में राजनीति के संत कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। इसके बाद दतिया के बीजेपी नेता अवधेश नायक, राजू दांगी और सुरखी के राजकुमार सिंह धनौरा, नीरज शर्मा को भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। बता दें कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और शिवपुरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस इन सभी का उपयोग बीजेपी में सेंध लगाने के लिए कर रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव के आते-आते कई बड़े नेता कांग्रेस के मंच पर नजर आ सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन नेताओं को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषिक किया है। उन पर भी कांग्रेस नजरें जमाए हुए है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों को उनकी अपनी सीट से टिकट भी दे सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक-कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी में आने के बाद से ही पार्टी के मूल कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। इस वजह से कार्यकर्ताओं और नेताओं की गाहे-बगाहे नाराजगी भी सामने आती रहती है। वहीं बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका नुकसान उठाना पड़ा था। असंतोष के स्वर को थामने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने की कवायद शुरू है। वहीं भाजपा नेताओं का कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेने का क्रम भी जारी है। वहीं कांग्रेस इस अवसर को भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि पार्टी के नाता यह बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। वहीं इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी से इस समय उपेक्षित भी हैं। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जोड़कर बीजेपी में सेंध लगाई जा सकती है। साथ ही राज्य में अपनी पार्टी की स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस की सदस्यता जिन नेताओं को दिलाई जा रही है, उनमें से कुछ को प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाए। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पिछले चुनाव में ऐसा कमाल कर चुकी है। बीजेपी ने कमलेश साहू की पार्टी प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन बीजेपी के असंतुष्ट गुट के लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। पर वह कांग्रेस के गोपाल भार्गव से पराजित हो गए। वहीं कांग्रेस के लिए भाजपा के असंतुष्टों को साधने का काम पूर्व मंत्री दीपक जोशी कर रहे हैं। उनकी कोशिशों के जरिए ही बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।कांग्रेस यही रणनीति शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा को घेरने के लिए के लिए अपना रही है। पार्टी द्वारा पहले अवधेश नायक और अब राजू दांगी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। उसके बाद ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में भाजपा और सिंधिया की घेराबंदी करने के लिए अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, नीमच जिले के यादवेन्द्र सिंह यादव, बैजनाथ यादव, अजय पाल सिंह यादव, समंदर पटेल, रघुराज सिंह धाकड़, जितेंद्र जैन सहित कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ पकड़ा है।

लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को किनारे करने का प्रयास

संतोष पाठक

राजनीतिक विज्ञान में लोकमत और बहुमत के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है और इसमें लोकमत को बहुमत से कहीं ज्यादा ऊपर रखा गया है। बहुमत कई बार आंकड़ों और ज्यादा आबादी के नाम पर खेल कर सकता है, दूसरों को दबा सकता है। बहुमत या ज्यादा संख्या का मतलब यह कतई नहीं होता कि उसके द्वारा किया गया हर कार्य जनता यानि लोगों के हित में, लोकमत है। क्योंकि बहुमत हमेशा सही होता है तो हमें इस आधार पर 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को भी सही ठहराना होगा क्योंकि जो इंदिरा सरकार इसे लेकर आई थी, उसके पास जनता द्वारा दिया गया बहुमत तो था ही। इसी तर्क पर हमें विभिन्न राज्यों और केंद्र की विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में हुए घोटालों को भी सही ठहराना पड़ेगा क्योंकि वे सारे फैसले किसी न किसी करीबी को फायदा पहुंचाने के लिए बहुमत वाली सरकारों ने ही तो लिए थे।

इसलिए बहुमत हमेशा लोकमत हो यह जरूरी नहीं है। लोकमत का अर्थ बहुमत या फिर सर्वसम्मति कतई नहीं होता बल्कि लोकमत का तात्पर्य बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज का हित होता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की चुनावी राजनीति में जो बुराइयां आ गई है उसमें से सबसे भयावह बुराई बहुमत का अहंकार है और अब इसी बुराई को जाति के नाम पर देश के लोगों के दिलों-दिमाग में भी बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और देश का कोई भी राजनीतिक दल खुल कर इसका विरोध करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। एक तरफ देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग करते हुए कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है, उसे उतना हक मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ बिहार में 1990 के बाद पिछले 33 सालों से बारी-बारी से राज करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव हैं जो मुसलमानों और पिछड़ों का

कल्याण करने के बाद अब अति पिछड़ों के कल्याण की बात कर रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुसंख्यकवाद के खतरे को समझा और अपनी पार्टी की राय से अलग जाकर सोशल मीडिया पर खुलकर देश को इस खतरे से आगाह करते हुए लिखा कि, अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी। लेकिन आनन-फानन में कांग्रेस ने न केवल अपने वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को उनका निजी विचार बताकर किनारा कर लिया बल्कि हालात ऐसे बना दिए गए कि सिंघवी को अपने पोस्ट को डिलीट तक करना पड़ गया। वास्तव में वह अपनी ही पार्टी में अल्पसंख्यक बन गए और पार्टी के फैसले यानि अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी के बहुमत के कारण उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक से वंचित होना पड़ा।

हालांकि सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरे भी हैं। लंबे समय तक आरक्षण की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों के नेता जान-बुझकर बाबा साहेब अंबेडकर के उस भाषण का जिक्र नहीं करते हैं जो उन्होंने आरक्षण की समयावधि को लेकर दिया था। बाबा साहेब की बात मानने की बजाय राजनीतिक फायदे के लिए ये दल आरक्षण का समयकाल और दायरा दोनों ही बढ़ाते जा रहे हैं। वास्तव में बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे के आंकड़े नीतीश कुमार और लालू यादव, दोनों के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए था कि 33 साल तक बिहार पर राज करने के बावजूद बिहार की यह हालत क्यों हैं कि- उन्हें पिछड़ा और अति पिछड़ा का राग अलापना पड़ रहा है ? आखिर क्यों बिहार से कुछ खास जातियों को बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा है ? अगर कुछ शिक्षित लोगों या जाति विशेष से जुड़े लोगों ने बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के खतरे को समझ कर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए तो उन्हें अपनी कम होती जनसंख्या का खामियाजा भुगतना पड़ेगा ? सामाजिक न्याय का मतलब वंचितों के जीवन स्तर को बढ़ा कर उन्हें समाज के अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना होता है या फिर उन्हें वंचित का वंचित बनाकर सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना होता है ? अगर पिछड़े वर्ग को मिल रहे आरक्षण का लाभ उसी वर्ग से आने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग को अभी तक नहीं मिल पाया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर जनसंख्या के आधार पर ही सब कुछ तय होना है और संसाधनों का बंटवारा होना है तो फिर योग्यता का क्या होगा ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने ही योग्य लोगों को एक बार फिर से प्रवास करने पर मजबूर करने जा रहे हैं ? पहले बिहार छोड़कर जाना पड़ा और अब देश छोड़कर जाने जैसे हालात पैदा कर रहे हैं ? क्या यह बेहतर नहीं होता कि लालू-नीतीश जातीय सर्वे के आंकड़ें जारी करने से पहले आंकड़ों के जरिए देश को यह बताते कि 33 सालों के राज में बिहार के कितने गरीबों का भला हुआ है, राज्य में कितने उद्योग-धंधे लगे हैं, कितने नए स्कूल-कॉलेज खुले हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है और आज मानव विकास के सभी सूचकांकों और पैमाने पर बिहार कहां खड़ा है ? लेकिन यह सवाल पूछेगा कौन क्योंकि बहुमत और लोकमत की लड़ाई में फिर से बहुमत हावी होता नजर आ रहा है और कोई भी राजनीतिक दल रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता है।

बेरोजगारी की समस्या का हल निकालना मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय सनातनी वेदों एवं ग्रंथो में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत सदैव ही आर्थिक रूप से सम्पन्न देश रहा है एवं भारत के समस्त नागरिकों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध रहे हैं। मुद्रा स्फीति, आय की असमानता, बेरोजगारी एवं ऋण के भारी बोझ के तले दबे रहना जैसे शब्दों का तो प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में वर्णन नहीं के बराबर मिलता है। भारत के समस्त नागरिकों की पर्याप्त मात्रा में आय होती थी जिससे वह अपने परिवार का आसानी से गुजर बसर कर पाते थे एवं समाज में समस्त नागरिक प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। दरअसल प्राचीन भारत के उस खंडकाल में नागरिकों में उद्यमशीलता अपने चरम पर थी। परिवार के जमे जमाए व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी सफलतापूर्वक आगे चलते रहते थे एवं परिवार के सदस्यों के आय अर्जन का मुख स्त्रोत बने रहते थे। इस दृष्टि से नागरिकों को सामान्यत: नौकरी के लिए परिवार के पारम्परिक व्यवसाय के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार उस खंडकाल में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती थी।

भारत पर आक्रांताओं के आक्रमण एवं इसके तुरंत बाद अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय नागरिकों की उद्यमशीलता को समाप्त कर उनमें नौकरी करने की भावना को विकसित किया गया क्योंकि अंग्रेजों को अपने शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए नौकरों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की शिक्षा पद्धति को भी कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया गया कि भारतीय नागरिक अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात अंग्रेजों के संस्थानों में केवल नौकरी कर सके। दीर्घकाल में इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नागरिक केवल नौकरी को ही रोजगार का साधन मानने लगे और उन्हें यदि नौकरी नहीं मिल पाती तो वे अपने आप को बेरोजगार मानने लगे। भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता तो जैसे समाप्त ही हो गई थी। परंतु, पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता को पुन: पैदा करने के अथक प्रयास किये गए हैं, जिनमे सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है और भारत में अब पुन: बहुत बड़ी मात्रा में उद्यमों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे भारतीय नागरिक अब धीरे-धीरे नौकर नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनते जा रहे हैं।

पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भारतीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सुरक्षित बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था। वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया योजना देश में लागू की गई थी। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना था, जो पूरे देश में उद्यमिता का पोषण और प्रचार करता हो। वर्ष 2016 में ही स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और एससी/एसटी उधारकर्ताओं को 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण की सुविधा तथा ग्रीनफील्ड उद्यम

स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रु. तक का ऋण प्रदान करना था। इसके पूर्व, वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना %कौशल भारत% एजेंडे को %मिशन मोड% में चलाने के लिए की गई थी ताकि मौजूदा कौशल प्रशिक्षण पहलों को एकजुट किया जा सके और कौशल प्रयासों के पैमाने और गुणवत्ता को गति के साथ जोड़ा जा सके। इन योजनाओं के साथ ही भारतीय नागरिकों और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सम्बोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं (पीएम गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, प्रसाद योजना, आदि) भी प्रारम्भ की गई हैं। विभिन्न सरकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारत में रोजगार के अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से कई अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर भी कुछ प्रयास प्रारम्भ किया गए। संघ ने तो अपने कुछ आनुषांगिक संगठनों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करें। इन सामाजिक, आर्थिक एंड सांस्कृतिक संगठनों ने मिलकर समाज में विशेष रूप से युवा नागरिकों के उद्यमशीलता को पुन: विकसित करने के सफल प्रयास किए हैं एवं अब एक बार पुन: भारत में उद्यमों को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी भविष्यनिधि संस्थान में रजिस्टर हुए नए सदस्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में 61 लाख थी जो वित्तीय वर्ष 1920-21 में 77 लाख, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 122 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 139 लाख हो गई है। इस संख्या में लगातार सुधार से आशय यह है कि देश में युवाओं को फोर्मल रोजगार बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। यहां इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान विश्व के अन्य देशों में कई कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी की गई है। इसी प्रकार पीरिओडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जनवरी 2022 से भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। जनवरी 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 8.2 प्रतिशत थी जो अप्रैल-जून 2022 तिमाही में घटकर 7.6 प्रतिशत तो वहीं जुलाई-सितम्बर 2022 तिमाही में 7.2 प्रतिशत, अक्टूबर-दिसम्बर 2022 तिमाही में 7.2 प्रतिशत से घटाकर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में 6.8 प्रतिशत पर आ गई है। सीएमआईई द्वारा जारी एक अन्य जानकारी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी की दर मार्च 2023 में घटकर 7.6 प्रतिशत हो गई है जो मार्च 2022 में 8 प्रतिशत एवं मार्च 2021 में 10 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक) में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में घटकर 9.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि एक वर्ष पहिले इसी तिमाही में 10.1 प्रतिशत थी। वहीं, पुरुषों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इस वर्ष पहली तिमाही में कम होकर 6 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पूर्व 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में 7.7 प्रतिशत थी।

देश में राज्यवार बेरोजगारी का विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि 10 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं, हरियाणा में 37.4 प्रतिशत, राजस्थान में 28.5 प्रतिशत, दिल्ली में 20.8 प्रतिशत, बिहार में 19.1 प्रतिशत, झारखंड में 18 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 14.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.3 प्रतिशत एवं सिक्किम में 13.6 प्रतिशत है। जबकि 5 प्रतिशत से कम बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं ओडिशा में 0.9 प्रतिशत, गुजरात में 2.3 प्रतिशत, कर्नाटक में 2.5 प्रतिशत, मेघालय में 2.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 3.1 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 3.2 प्रतिशत, छतीसगढ़ में 3.4 प्रतिशत, तेलंगाना में 4.1 प्रतिशत, उत्तराखंड में 4.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 4.3 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.7 प्रतिशत, आसाम में 4.7 प्रतिशत एवं पुडुचेरी में 4.7 प्रतिशत। विशेष रूप से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य, जो कुछ वर्ष पूर्व तक बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल थे, में बेरोजगारी की दर में अतुलनीय रूप से कमी दृष्टिगोचर हुई है। जनवरी-मार्च 2023 अवधि में देश में 45.2 फीसदी नागरिकों को रोजगार मिला हुआ है जो इससे पहले की तिमाही में 44.7 फीसदी पर था। उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई है। स्पष्ट है कि सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी संबल प्रदान करने की तमाम कोशिशें की हैं।

सर्वपितृ अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग

ऐसे करें पितरों की विदाई

पितृ पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है यह श्राद्ध की सबसे अहम और आखिरी तिथि होती है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन अमावस्या के दिन हुआ हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो। पितृ पक्ष के दिनों में अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हों तो पितृ दोष से बचने के लिए अमावस्या के दिन उनका भी श्राद्ध किया जा सकता है।

इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर, शनिवार के दिन है। पितृ पक्ष की अमावस्या पर इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। माना जाता है कि इन योगों में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से वह कई सालों तक तृप्त रहते हैं।

सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 13 अक्टूबर को 9 बजकर 51 मिनट से
अमावस्या तिथि समाप्त: 14 अक्टूबर, शनिवार की रात 11 बजकर 25 मिनट पर

सर्वपितृ अमावस्या पर दुर्लभ संयोग

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल 14 अक्टूबर को पितृ पक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या के दिन शनिवार होने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस दिन शुभ इंद्र योग भी बन रहा है। सर्वपितृ अमावस्या अश्विन माह में पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इन शुभ संयोगों में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है।

ऐसे करें पितरों को विदा

सर्वपितृ अमावस्या तिथि को ही पितृ पक्ष का समापन होता है। इस दिन प्रात: स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करें, इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। माना जाता है कि जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है।

इन लोगों को जरूर कराएं भोजन

घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबलि अर्थात गाय, कुत्ते, कौए, देव एवं चीटिंयों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए।

श्रद्धापूर्वक पितरों से मंगल कामना करें। इस दिन ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन बहन, दामाद और भांजा-भांजी को भी भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है कि उनके भोजन के बिना पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। भोज के बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने-अनजाने हुई भूल के लिए माफी मांगनी चाहिए।

मातृ नवमी 7 को

जानें महत्व और इस दिन जरूर करें ये काम

7 अक्टूबर दिन शनिवार को मातृ नवमी का श्राद्ध व तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष में मातृ नवमी तिथि का विशेष महत्व है इस दिन मृत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि शुभ काम किए जाते हैं। यह तिथि हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को नौमी श्राद्ध या अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है, उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। आइए जानते हैं मातृ नवमी का महत्व और शुभ तिथि ।

मातृ नवमी का महत्व

मातृ नवमी के दिन दिवंगत माताएं, बहुएं और बेटियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो यानी जिनके पति जीवित थे। इस दिन इन महिलाओं का श्राद्ध करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृ शक्ति प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबलि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए।

नवमी तिथि का प्रारंभ - 7 अक्टूबर, सुबह 08 बजकर 09 मिनट शुरू
नवमी तिथि का समापन - 8 अक्टूबर, सुबह 10 बजकर 13 मिनट तक

पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किए जाते हैं इसलिए 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मातृ नवमी मनाई जाएगी। मातृ नवमी के दिन शिव नामक शुभ योग बन रहा है और बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

मातृ नवमी पूजा विधि

मातृ नवमी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए। पितरों का श्राद्ध कर्म 12 बजे के आसपास किया जाता है। दोपहर के समय कंडा को जलाकर सभी परिवार वाले दिवंगत महिलाओं को याद करते हुए घी, खीर-पूड़ी, गुड़ आदि चीजें अर्पित करें। धूप दीप करने के बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। फिर मृत परिजन को याद करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पंचबलि के लिए भोजन निकालें और घर आई महिला का आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोपहर के समाप्त होने से पहले सभी श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लेने चाहिए।

मातृ नवमी के दिन जरूर करें ये काम

मात नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे कि पितरों से जुड़े कार्यों के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब व जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां अनाज, जूते चप्पल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन घर आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के जाने नहीं देना चाहिए।

साल भर में एक बार खिलता है ब्रह्म कमल

इन उपायों से लोगों की भर देता है झोली

हिंदू धर्म में कमल फूल का विशेष महत्व है। कमल का फूल सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल के फूल कई तरह के होते हैं लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चमत्कारी है ब्रह्म कमल का फूल। ब्रह्म कमल का फूल साल भर में एक बार उगते हैं और केवल चार से पांच घंटे के लिए खिलते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म कमल के फूल को खिलते हुए देख लेता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और जिस घर में ब्रह्म कमल का फूल खिलता है, वहां मां लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म कमल फूल का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी धन की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। आइए जानते हैं ब्रह्म कमल के उपाय के बारे में...

त्रिदेवों का मिलता है आशीर्वाद

ब्रह्म कमल फूल को ब्रह्मदेव का रूप माना जाता है और जब यह फूल खिलता है तो भगवान विष्णु की आकृति इस फूल पर दिखाई देती है। मान्यता है कि शिवजी ने ब्रह्म कमल से ही जल छिड़ककर गणेशजी को जीवित कर दिया था इसलिए इसे जीवन देने वाला फूल भी माना जाता है।

भगवान शिव को अति प्रिय हैं यह फूल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान शिव को ब्रह्म कमल का फूल अर्पित करने से इसका फल तुरंत मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान शिव को सफेद रंग का ब्रह्म कमल का फूल अति प्रिय है। भगवान विष्णु ने यही फूल शिवजी को अर्पित किए थे। इस फूल को जो भी खिलते देख लेता है उसका भाग्य खुल जाता है।

घर में लगाने से बनी रहती है समृद्धि

ब्रह्म कमल का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह फूल जिस घर में खिलता है, वहां सम्पन्नता और समृद्धि बनी रहती है। इस फूल में मां लक्ष्मी के वास होने से धन वृद्धि के योग बनते हैं और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। मान्यता है कि इस फूल की पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं, जिससे घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण रहता है।

कई तरह के रोग दूर करता है ब्रह्म कमल

ब्रह्म कमल के फूल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह कैंसर, सर्दी जुकाम, काली खांसी, थकान मिटाने में काम आता है।

इसके साथ ही यह शरीर में ब्लड प्यूरीफाई यानी खून साफ भी करता है और सांप काटने का इलाज, प्लेग का इलाज, हार्ट से संबंधित विकारों के इलाज में काफी मदद करता है। ब्रह्म कमल में एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं, जो चोटों के घाव भरने के लिए ठीक करने में मदद करता है।

भगवान विष्णु ने अर्पित किए 1000 ब्रह्म कमल के फूल

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 ब्रह्म कमल अर्पित किए थे, जिनमें से एक फूल कम हो गया था। तब भगवान विष्णु ने फूल के रूप में अपनी एक आंख भगवान शिव को समर्पित कर दी थी। तब से भोलेनाथ को कमलेश्वर और भगवान विष्णु कमल नयन का नाम पड़ा।

हिंदू धर्म में कमल फूल का विशेष महत्व है। कमल का फूल सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल के फूल कई तरह के होते हैं लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चमत्कारी है ब्रह्म कमल का फूल। ब्रह्म कमल का फूल साल भर में एक बार उगते हैं और केवल चार से पांच घंटे के लिए खिलते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म कमल के फूल को खिलते हुए देख लेता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और जिस घर में ब्रह्म कमल का फूल खिलता है, वहां मां लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म कमल फूल का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी धन की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। आइए जानते हैं ब्रह्म कमल के उपाय के बारे में...

बुलंद रहे धर्म की पताका

धर्म एक आदत के समान है। इसका स्वयं पालन करना आवश्यक है, लेकिन दूसरों को पालन करवाने के लिए ज़बरदस्तीकरना नहीं चाहिए। धर्म का विस्तार धर्म के अनुसार ही होना आवश्यक है यदि आप धर्म के विस्तार के लिए अधर्म कर रहे हैं तो आपका धर्म पहले ही नष्ट हो चुका है। धर्म का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस समाज में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। धर्म व्यक्ति के मष्तिष्क से मोह-माया को समाप्त कर उन्हें जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत करवाता है। धर्म विश्वास पर आधारित है कृपया इसका आधार अंधविश्वास को ना बनाएँ। धर्म की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है मानव हानि के लिए नहीं। अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही अपने धर्म को निभाना है। मानव धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। उपरोक्त बातों पर गहन विचार करने के बाद हमें लगा कि आज-कल के भाग-दौड भरे जीवन में पर्व और तिथियाँ याद रखना चुनौती बन गया है। इसलिए आपकी चुनौती का समाधान करने का बीडा हमने उठाया है। इसके तहत पाठकों को प्रतिदिन के व्रत-त्योहार की जानकारियाँ एक जगह समेट कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं।

– संजना अग्रवाल

धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो.... !

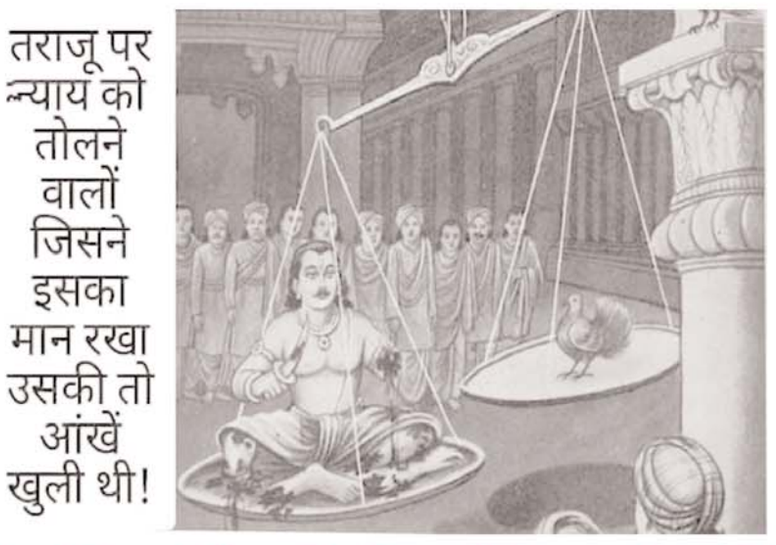

धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए! इसके लिए इस गौरवशाली इतिहास को पढ़ना चाहिए, देश और धर्म से आंतरिक नाता है तो हमारे पूर्वज ऐसे थे।

धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए! इसके लिए इस गौरवशाली इतिहास को पढ़ना चाहिए, देश और धर्म से आंतरिक नाता है तो हमारे पूर्वज ऐसे थे। गर्व से कहो हम हिन्दू हैं।।

पुरुवंश में जन्मे उशीनर देश के राजा शिवि बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे जो भी याचक उसने द्वार जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था प्राणिमात्र के प्रति राजा शिवि का बड़ा स्नेह था अतः उनके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था राजा शिवि हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे राजा शिवि की परोपकार शीलता और त्याग वृति के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे।

देवताओं के मुख से राजा शिवि की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ अतः उन्होंने उशीनरेश की परीक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया दोनों उड़ते-उड़ते राजा शिवि के राज्य में पहुँचे ।

उस समय राजा शिवि एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे कबूतर उड़ते-उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवि की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला राजन ! मैं आपकी शरण आया हूँ मेरी रक्षा कीजिये।

थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे-पीछे बाज भी वहाँ आ पहुँचा और बोला राजन ! निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा है आप कृतघ्न को धन से झूठ को सत्य से निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते है इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं और आप अजातशत्रु नाम से प्रसिद्ध है आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते है आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते है ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे है ? मैं क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे है यह आप अधर्म कर रहे है कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिये यह मेरा भोजन है।

इतने में कबूतर बोला शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है अतः आप इस बाज की बात कभी मत मानिये यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा।

दोनों की बात सुनकर राजा शिवि बाज से बोले हे बाज यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण आया है अतः यह मेरा शरणार्थी है मैं अपनी शरण आये शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते है सज्जन लोग उनकी निंदा करते है और उनको ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है।

जैसे हमें अपने प्राण प्यारे है वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे है समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्युभय से भयभीत जीवों की रक्षा करें अतः हे बाज ! मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो मैं तुझे वह अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ।

तब बाज बोला हे राजन ! मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ आप तो जानते ही है भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है यदि मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जायेंगे आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है हे राजन ! आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे है जो अधर्म को जन्म देने वाला है बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते है जो दुसरे धर्म का हनन न करें आप अपने विवेक के तराजू से तोलिये और जो धर्म आपको अभीष्ट हो वह मुझे बताइए।

राजा शिवि बोले हे बाज ! भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथासमय नष्ट हो जाता है किन्तु भयाकुल प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता अतः मैं अपने सम्पूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ परन्तु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता हे बाज ! तुझे आहार ही अभीष्ट है सो जो चाहो सो आहार के लिए मांग लो।

बाज बोला हे राजन ! प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है अतः आप इसे त्याग दीजिये।

राजा बोला हे बाज ! मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है परोपकार पूण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ परन्तु ये कबूतर नहीं दे सकता।

तब बाज बोला ठीक है राजन ! यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिये जिससे मैं अपनी क्षुधा शांत कर सकूं मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए।

प्रसन्न होते हुए राजा शिवि बोला हे बाज ! तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दुसरे पलड़े में वह अपना मांस काटकर रखने लगे लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ ही रहा।

तब अंत में राजा शिवि स्वयं उस पलड़े में बैठ गये और बोले हे बाज ! ये लो मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी मृदंग बजने लगे स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे यह देखकर राजा शिवि विस्मय से सोचने लगे कि इस सबका क्या कारण हो सकता है ? इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गये और अपने असली रूप में प्रकट हो गये।

इंद्र ने कहा हे राजन ! आपके जैसा धर्म परायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्नि है जो कबूतर बना था हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आये थे हे राजन ! ऐसे मनुष्य विरले ही होते है जो दूसरों उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते है किन्तु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जिता है इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गये ।

राजा शिवि ने अपना यज्ञ पूरा और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परमपद को प्राप्त हुए है।

प्रस्तुति : मनोज शर्मा
फ़ोन : 86391 30737

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संजय सिंह की गिरफ्तारी से यूपी में भी गरमाई राजनीति

लखनऊ। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य एवं पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह के घर पर ईडी के छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अपने नेता के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के विरोध में आप कार्यकर्ता सड़क पर उतर आया है। वहीं अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। आप के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ है उसे गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन में पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी हुई। भाजपा ये समझ ले कि इस बार 100 करोड़ लोग उनके खिलाफ हैं। इस बार इंडिया इसी भाजपा का सफाया करेगी। ईडी, सीबीआई , और आइटी इनके (भाजपा) संगठन के हिस्से हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सपा सुप्रीमो कहते हैं, सरकार सोचती है कि जो विरोध में हैं उन्हें गिरफ्तार करो, नेताओं को गिरफ्तार करो।

आप की फितरत खुलेआम घोटाले करने की है : पात्रा

नईदिल्ली। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को पार्टी के तीसरे नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आप पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी की खुलेआम घोटाले करने की प्रकृति है। पात्रा ने ओडिशा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, मीडिया सूत्रों के अनुसार, संजय सिंह के घर से प्राप्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेज़ आप के पदानुक्रम में शीर्ष पर मौजूद किसी व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे। पात्रा ने आगे कहा, जब भ्रष्टाचार का कोई डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए जाते हैं, जो मोबाइल फोन और लैपटॉप में रखे होते हैं, जहां तक आपत्तिजनक दस्तावेजों की बात है जो संजय सिंह के घर से हासिल किए गए हैं, ये दस्तावेज़ उस व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे जो आप श्रृंखला में बहुत बड़ा है।

हम डरने वाले नहीं : आतिशी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले आप नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि इस जांच में ईडी और सीबीआई ने पिछले 15 महीने से 500 से ज्यादा अफसरों को लगाया है। ये अफसर हजारों जगहों पर छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि ये अदालत में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। आतिशी ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसौदिया के कार्यालय और आवास पर छापा मारा और कुछ नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के किसी भी सबूत के बिना, मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहानी संजय सिंह के साथ दोहराई जा रही है।

हमारी एकजुटता से डरी हुई है भाजपा : स्टालिन

चेन्नई। डीएमके सांसद जगतरक्षकन के आवास पर आयकर छापे पर पहली प्रतिक्रिया में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके सांसद जगतरक्षकन के खिलाफ छापेमारी और आप सांसद की गिरफ्तारी इंडिया ब्लॉक नेताओं के खिलाफ राजनीतिक लाभ के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के स्पष्ट उदाहरण हैं। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न लोकतंत्र पर हमला है। एक्स पर स्टालिन ने कहा कि केंद्र भाजपा सरकार की प्रतिशोधात्मक राजनीति की कोई सीमा नहीं है। भाजपा आसानी से भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी ईडी को पारदर्शी और निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे कानून के शासन और लोकतंत्र की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं। सीएम ने कहा, बीजेपी विपक्षी दलों के बीच बढ़ती एकजुटता से साफ तौर पर डरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपना जादू-टोना बंद करें और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।

सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई अब 12 को होगी

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का आज दूसरा दिन था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को फायदा मिलने की बात कही जा रही है तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है?

राजस्थान में बोले प्रधानमंत्री- भाजपा आएगी, खुशहाली लाएगी

लाल डायरी में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की काली करतूत : मोदी

जयपुर। राजस्थान चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर दौरे पर है। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। एक उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएंगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। ये फैसला रसोई को धुएं से मुक्त करने के हमारे अभियान को भी मजबूती देगा।

मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 राज्य बनाने का है। ये काम मोदी नहीं बल्कि आपके एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत से भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान पर्यटन में नंबर 1 बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रही है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ इस क्षेत्र को होने वाला है। हम राजस्थान के कोने-कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे।

मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसलिए राजस्थान कह रहा है- भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी जोधपुर में ही करीब 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकर्पण करके आया हूं। ये एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। मुख्यमंत्री इसलिए गायब थे क्योंकि उनको भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक

हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है। लेकिन यहां की स्थिति देखकर दुख होता है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे रखी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। अपना हमला जारी रखते हुए मोदी ने कहा कि आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत इस लाल डायरी में दर्ज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लाल डायरी का राज सामने आए, तो आपको यहां भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा... आपने लाल डायरी के बारे में सुना होगा, लोग कहते हैं लाल डायरी में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की काली करतूत है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ भाजपा सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर लीक माफिया को मिटाएगी। प्रधघानमंत्री ने कहा कि जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन-दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण करके उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। कांग्रेस की ही एक विधायक कहती है कि वह सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन-बेटियों की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टिकरण है? राम नवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाज़ी की खबरें न आती हों।

5,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और कहा कि भारत सरकार आज राज्य में रेल, रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,''ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो।' यह समारोह जोधपुर शहर में आयोजित किया गया जहां मोदी ने रिमोट बटन दबाकर परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा,'बीते नौ वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देखे रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में रेल, रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है।

विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना अब भाजपा को बदलने का समय: प्रियंका

भोपाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने मध्य प्रदेश के धार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह कई महापुरुषों की भूमि है। हम उन्हें महापुरुष कहते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर जनता के हितों के लिए संघर्ष किया और कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहां व्यापमं घोटाला हुआ। क्या कोई जांच कराई गई? अगर आप उनके (बीजेपी) खिलाफ लिखते हैं तो ईडी तुरंत पहुंच जाती है। आपको पूछना होगा कि ईडी अभी तक यहां क्यों नहीं आई? जब माँ नर्मदा के साथ और सप्तऋषियों की मूर्तियों के संबंध में (महाकाल गलियारे में) भ्रष्टाचार हो सकता है...क्या भगवान के साथ भी कोई भ्रष्टाचार करता है? क्या अब उन्हें (बीजेपी को) बदलने का समय नहीं आ गया है?

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज आदिवासी समाज की गौरव और गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती है। उन्हें मेरा शत-शत नमन। आदिवासी नायक भीमा नायक जी, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी और बादल भोई जी की विरासत को नमन। यह महाराजा भोज की धरती है। शहीद महाराजा बख्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज व राष्ट्र के नायक टंट्या मामा ने आजादी के लिए प्राणों का बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर जी की भी धरती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का यहां से पुराना रिश्ता रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं सुबह उठकर देखी कि मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं। हम जो कहते है, वो भी वहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने रोजगार दिलाए हैं। हम कहते हैं कि हमने दिलाएं। ऐसे में जनता को कैसे पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों में 17 हजार नवयुवकों ने खुदकुशी की है। मेरी बातों में भी मत पड़िए। सच्चाई और अपने

अनुभव में पड़िए। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश पर गर्व है क्योंकि हमारा देश ऐसा था जिसका लोकतंत्र पड़ोसी देशों में सबसे मजबूत माना जाता था। संविधान लिखने वाले लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। हमें अपने देश पर गर्व है जिसका संविधान है लिखा कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने पंचायतों को अधिकार देकर इस अधिकार को मजबूत बनाया।

इसके आलावा प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सरकार बनने पर कई योजनाएं शुरू करने की गारंटी दी। उन्होंने कहा- प्रदेश में कांग्रेस सरकारा बनने के बाद किसानों के कर्ज फिर से माफ करेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। 200 यूनिट बिजली हाफ दर पर मिलेगी। पुरानी पेंशन फिर से लागू करेंगे। 5 हार्स पावर बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह खाते में मिलेंगे। प्रियंका ने कहा कि चुनाव आते ही सरकार ने घोषणाएं शुरू कर दी है। मोदीजी हर दो दिन में आकर उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल से ये याद क्यों नहीं आया। क्या उन्हें समय नहीं मिला। जागो और इनको सिखाओ। ये किसानों के जीवन में मुश्किल डाल रहे हैं कि ये भीख मांगे। बेरोजगारी चरम पर है।

खेल
प्रमुख समाचार

तीरंदाजी स्पर्धा में एक और स्वर्ण, झोली में 21वां गोल्ड

हांगझोऊ। भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने गुरुवार को यहां फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर स्क्वाश मिश्रित युगल का खिताब जीता।

भारत की परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गुरुवार को हांग्जो में एशियाई खेलों 2023 में तीरंदाजी महिला टीम कंपाउंड स्पर्धा में चीनी ताइपे को 230-229 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत को 19वां स्वर्ण दिलाया था। दीपिका पल्लीकल और हरिंदरपाल सिंह संधू की भारतीय स्क्वैश जोड़ी ने 20वां स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी सुनिश्चित किया। दीपिका और हरिंदर ने फाइनल में आइफा बिंटी अजमन और मोहम्मद सयाफिक बिन मोहम्मद कमल को 35 मिनट में 11-10 11-10 से हराया। भारत ने 2014 में पुरूष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था जो टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने इंचियोन में दो रजत और एक कांस्य भी जीता था। दीपिका ने जीत के बाद कहा ,'मुझे हमेशा याद नहीं रहता कि कोर्ट पर क्या हुआ। हमें सिर्फ आखिरी अंक याद रहता है। हम बहुत खुश हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम स्वर्ण पदक जीत सके।' दूसरे गेम में एक समय भारतीय जोड़ी आसान जीत की ओर से बढ़ रही थी लेकिन इसके बाद उनकी एकाग्रता टूटी जिससे मलेशिया की जोड़ी मुकाबले को करीबी बनाने में सफल रही। मलेशिया की जोड़ी ने 3-9 के स्कोर पर लगातार सात अंक से 10-9 की बढ़त बनाई लेकिन दीपिका और हरिंदर ने धैर्य बरकरार रखते हुए लगातार दो अंक के साथ जीत दर्ज की। एशियाई खेलों में संभवत: अंतिम बार खेल रही दीपिका ने अपने अभियान का अंत दो पदक के साथ किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 406 अंक चढ़ा निफ्टी भी 19,500 के पार

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले मिश्रित रूझानों के बीच हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में दो दिन से जारी गिरावट के सिलसिले पर ब्रेक लग गया। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 406 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 110 अंकों की बढ़त देखी गई। व्यापक बाजारों में, मिडकैप सूचकांक 0.03 प्रतिशत नीचे रहा। वहीं दूसरी ओर स्मॉलकैप सूचकांक 0.6 फीसदी ऊपर रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 405.53 अंक यानी 0.62 फीसदी की बढ़त के साथ 65,631.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,753.20 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,443.34 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी में भी 109.65 अंक यानी 0.56 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

सितंबर में 13 सालों के हाई लेवल पर सर्विस पीएमआई

नईदिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मजबूत मांग के चलते सर्विस पीएमआई सितंबर में 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। वहीं समग्र व्यापार में सुधार के कारण नौकरियों बढ़ रही हैं। एक मासिक सर्वेक्षण में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल भारत सर्विस पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त के 60.1 से बढ़कर सितंबर में 61 पर पहुंच गया। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की करीब 400 कंपनियों को भेजे गए प्रश्नावली के जवाबों पर आधारित है। नए आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेवा प्रदाताओं के साथ नए कारोबार में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो जून 2010 के बाद से दूसरी सबसे तेज वृद्धि है।

ऐपल के सीईओ टिम कुक ने बेचे 5 लाख से ज्यादा शेयर

नईदिल्ली। ऐपल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में बड़ी संख्या में अपने शेयर बेचे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुक के शेयरों की इस बिक्री के बारे में यूएस सिक्योरिटीज फाइलिंग से पता चला है। फाइलिंग के अनुसार कुक ने 511,000 शेयर बेचे हैं, जिनकी कीमत टैक्स निकालने से पहले लगभग 8.78 करोड़ डॉलर थी। यानी कि इस बिक्री से उन्हें टैक्स निकालने के बाद 4.15 करोड़ डॉलर मिले हैं। भारतीय मुद्रा में ये करीब 345.38 करोड़ रुपये होता है। इतनी भारी संख्या में शेयर बेचने के बाद अब कुक के पास ऐपल में लगभग 33 लाख शेयर रह गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 56.5 करोड़ डॉलर है। बता दें, कुक ने करीब 2 सालों के बाद इतनी बड़ी बिक्री की है। इसके पहले अगस्त 2021 में स्टॉक बिक्री से 35.5 करोड़ डॉलर कमाए थे। कुक ने शेयर बेचे जरूर हैं लेकिन इस बिक्री से ऐपल कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी पर कोई असर नहीं होगा।

विशेषज्ञों की राय, रीपो दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बुधवार से शुरू हुई तीन दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के बीच विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि मुद्रास्फीति और अन्य वैश्विक कारकों के बीच केंद्रीय बैंक नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर ही कायम रख सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली एमपीसी बैठक के निर्णय की घोषणा शुक्रवार सुबह होगी। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने कहा, मुझे लगता है कि अगस्त में पिछली एमपीसी बैठक और इस समय के बीच मुद्रास्फीति बढ़ गई है, वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जबकि वैश्विक कारक इस अर्थ में थोड़े प्रतिकूल हो गए हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब भी अपने रुख में आक्रामक है। ऐसे में आरबीआई द्वारा नीतिगत दर को यथावत रखने की उम्मीद है।

आर्थिक वृद्धि के लिए बचत भी जरूरी

अजीत रानाडे

गरीबी घटाने के लिए आर्थिक वृद्धि बढ़ाना जरूरी होता है ताकि रोजगार और आय बढ़ सके। भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना 3000 डॉलर या लगभग 2.4 लाख रुपये है जो जी-20 देशों में सबसे कम है। विकास के एक उपयुक्त स्तर तक पहुंचने के लिए भारत की राष्ट्रीय आय हर साल सात से आठ प्रतिशत की दर से बढ़नी चाहिए। इसकी वास्तविक गणना के लिए महंगाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा कम-से-कम कुछ दशकों तक होना चाहिए। साथ ही, इस आय का वितरण भी समान होना चाहिए तथा मौजूदा असमानता और नहीं बढ़नी चाहिए। ऊंची आर्थिक वृद्धि के लिए राष्ट्रीय बचत सबसे जरूरी चीजों में एक होती है। यह राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा होती है, जिससे भविष्य के लिए निवेश किया जाता है। भारत की अब तक की सर्वाधिक राष्ट्रीय बचत वर्ष 2010-11 में की गयी थी जब यह जीडीपी का लगभग 37 फीसदी थी। अभी यह 30 प्रतिशत है। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत आम घरों से आता है, जिसमें छोटे कारोबारी भी शामिल हैं। बचत का बड़ा हिस्सा अमीर घरों से आता है, क्योंकि गरीब घरों के लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं। महंगाई बढ़ने पर कमाई और घट जाती है, और यदि आय महंगाई की दर से कम गति से बढ़ती है तो इससे भी लोगों की बचत घटती है।

भारत के कुल बजट को पारंपरिक तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है - वित्तीय और गैर-वित्तीय बचत। गैर-वित्तीय बजट से लोग जमीन-मकान या सोना खरीदते हैं। वित्तीय बजट बैंकों, म्यूचुअल फंड, बांड, पेंशन और बीमा में इस्तेमाल होता है। वित्तीय क्षेत्र की मजबूती से लोगों का भरोसा बढ़ता है और लोग सोना, जमीन की जगह लोग पैसे बैंकों

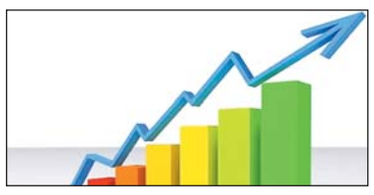

में या दूसरी चीजों में निवेश करते हैं। सोना महंगाई को मात देने के लिए किया गया निवेश माना जाता है। दुनिया में सोने की सबसे ज्यादा मांग भारत में होती है। लेकिन सोने के आयात से कीमती विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। भारत में घरेलू बचत का ज्यादा इस्तेमाल गैर-वित्तीय स्रोतों में हो रहा है, और इस स्थिति को पलटे जाने की जरूरत है। अगर लोग सोना कम और घर-जमीन ज्यादा खरीदते हैं तो समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा है। लेकिन, वित्तीय बचत की तुलना में यह अभी भी कम उत्पादक होता है क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था का पैसा बाजारों में असल पूंजी बनकर जाता है, जिससे नये कारखाने और परियोजनाएं बढ़ती हैं। वित्तीय बचत जब कम होती है तो बैंकों के पास कर्ज देने की राशि भी कम हो जाती है, जिससे ब्याज दर बढ़ जाती है। इस कमी की भरपाई विदेशी निवेश या कर्ज से होती है, लेकिन इससे देश डॉलर के कर्ज में फंस जाता है। किसी देश की सकल वित्तीय बचत से ही कर्ज दिये जाते हैं। यह वर्ष 2022-23 में घटकर जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रह गयी है, जो लगभग 50 सालों में सबसे कम है। ये बहुत चिंताजनक है। वर्ष 2020-21 में यह 11.5 प्रतिशत थी, जो अगले साल घटकर 7.2 और अभी 5.1 प्रतिशत पर आ गयी है। मगर इसी अवधि में कर्जों में तेजी से वृद्धि हुई है। लोग बैंकों और गैर-बैंकिंग स्रोतों से कर्ज ले रहे हैं। लोग बैंकों से पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन और वाहन लोन ले रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा गैर-बैंकिंग संस्थानों से कर्ज लिये जा रहे हैं। आज हमारे फोन पर अक्सर ऐसे कर्जों के लिए कॉल आते रहते हैं। लेकिन क्या गैर-बैंकिंग स्रोत ज्यादा जोखिम तो नहीं उठा रहे? अगर कहीं उनका बुलबुला फूटा तो अर्थव्यवस्था गिरनी तो नहीं शुरू हो जाएगी? सकल वित्तीय बचत में गिरावट चिंताजनक स्थिति है। और ये कहकर दिलासा नहीं दिया जा सकता कि यह स्थिति यह जताती है कि लोग निजी और होम लोन लेने के इच्छुक हैं। देश की सकल बचत तो कम है ही, केंद्र और राज्य सरकारें उसपर से लगातार कर्ज लिए जा रही हैं। भारत जे पी मॉर्गन बांड इंडेक्स में शामिल होने के बाद अभी लगभग 20 अरब डॉलर का नया कर्ज उठाने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन, बचत दर और सकल वित्तीय बचत में आयी कमी की स्थिति को पलटना बहुत जरूरी है। इसके लिए महंगाई को कम और स्थायी करने तथा वित्तीय कर्ज पर लगाम लगाने की जरूरत होगी।

अस्पताल के बाहर सुबह प्रसव होना बदहाल हो चली स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर

मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य महकमा संवेदनहीनःसरोज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. सरोज पांडेय ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालय अंबिकापुर में एक महिला द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर सुबह बच्चे को जन्म देने की खबर को प्रदेश की बदहाल हो चली स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर बताया है। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि जब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के अपने ही इलाके में जब स्वास्थ्य महकमा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रहा है तो प्रदेश के दीगर इलाकों की बदहाली का अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की संजीदगी से जाँच होनी चाहिए कि जब बुधवार देर रात रघुनाथपुर (बलरामपुर) निवासी गर्भवती पवित्रा (20) को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो गुरुवार की सुबह मेडिकल कॉलेज के बाहर

महिला ने किन अव्यवस्थाओं के चलते बच्चे को जन्म देने के लिए विवश हुई? गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अस्पताल का शौचालय गंदा होने के कारण महिला टॉयलेट के लिए बाहर चली गई। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद महिला ने वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती महिला के पति का यह आरोप बेहद गंभीर है कि अस्पताल के स्टाफ ने हमारी कोई मदद नहीं की। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने महिला के पति के आरोपों पर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के उस कथन को गैरजिम्मेदाराना बताया कि अस्तपाल के बाहर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल, बच्चे की हालत गंभीर है। उसे एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है। महिला के पति का यह आरोप भी स्वास्थ्य विभाग में चल रही भर्राशाही का परिचायक है कि प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल स्टाफ को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस दौरान अस्पताल के बाहर अन्य महिलाओं ने उसकी दिक्कत देखी तो वो मदद के लिए आगे आईं। उन्होंने ही उसकी पत्नी का प्रसव कराया। बच्चे की हालत ठीक नहीं है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं का शिकार है। कुछ समय पहले वहां भोजन की अव्यवस्था को लेकर बात सामने आई थी।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाएँ बदतर हुई हैं। गर्भवती महिलाओं को बेहतर व त्वरित सुविधा के लिहाज से शुरू की गई महतारी एक्सप्रेस भी दम तोड़ रही है। शुरुआत में इस योजना के तहत जहाँ लगभग साढ़े 3 सौ एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नाकारापन के चलते अब महज 1 सौ एंबुलेंस ही संचालित की जा रही है। यह प्रदेश सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के दावों पर करारा तमाचा है। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने दीगर वादों की ही तरह स्वास्थ्य संबंधी वादों से भी मुँह मोड़कर निर्लज्जता की हदें पार कर दीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खास मौजूदगी में प्रदेश सरकार ने जिस सर्वजन स्वास्थ्य योजना (युनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम) लागू की गई थी, वह प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इस योजना के तहत कितने लोगों को जाँच की सुविधा और दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की गईं? डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त डॉक्टर्स, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती की जाएगी। पूरा कार्यकाल बीतने को है, प्रदेश सरकार बताए कि प्रदेश के अमूमन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों, दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों के संकट से जूझ रहे हैं।

भाजयुमो की विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह ने ली बैठक

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में हमारे अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह ,प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पिता बडजेना, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमनदीप सिंह, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य व छग भाजयुमो प्रभारी दीप ज्योति मुंड, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य शशांक राज व प्रदेश महामंत्री अंकित जायसवाल के दीप प्रज्वलित कर के ,महापुरषों को माला अर्पण कर बैठक की शुरुवात किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भाजयुमो की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया भाजयुमो लगातार जमीनी स्तर में संघर्ष कर रहा है , पीएससी घोटाला, वन भर्ती घोटाला, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के साथ अनाचार, , चाकू बाजी, ऐसे तमाम घटनाओं को लेकर के

भाजयुमो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। जनता के हक की लड़ाई में कोई भी कमी हमने नहीं किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नव मतदाता सम्मेलन भी पूरे प्रदेश में चल रहा है परिवर्तन यात्रा में भी भाजयुमो की बड़ी भूमिका रही। रवि भगत ने कहा आने वाले चुनाव में युवा हमारे पक्ष में भाजयुमो से जुड़ रहा है। बूथ शक्ति केंद्र तक एक बूथ 20 युथ भी हमारा बन चुका है। राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह ने बताया 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी रायपुर आ रहे है। जिसमे मंडल अध्यक्ष ,महामंत्री, जिला अध्यक्ष ,महामंत्री और प्रदेश पदाधिकारी सबका एक संगठन कार्यशाला होना है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जिनका प्रवास जिम्मेदारी चुनाव तक छः ग में है उस सब को संभग वर जिम्मेदारी दे कर के प्रवास करना है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की प्रान्तीय कार्यशाला भी की जानी है।हर जिले से लोगों से बात चीत कर के भाजपा के पक्ष में माहौल बनायेगे।।संगठनात्मक प्रवास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।भाजयुमो के ऊपर पार्टी को सबसे ज्यादा भरोसा है उस भरोसे को कायम रखेंगे हमें अपने कार्य को और तेजी से करना है । प्रदेश पदाधिकारियों को अच्छे से मजबूती से कार्य जमीनी स्तर में जैसे कर रहे है उस गति को आगे बढ़ाए और 11अक्टूबर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से रायपुर शहर में हो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पिता ने कहा कि हमे नवीन प्रकार की योजना होनी चाहिए छोटी छोटी युथ बैठक होनी चाहिए। सुशांत शुक्ला ने बताया भाजयुमो ने बहुत अच्छे से तरीके परिवर्तन यात्रा में बहुत अच्छी भूमिका निभाया गया। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को अब नए काम अपने जिला प्रभार में अब मेहनत करना है। प्रवास बढ़ाना है जिले मंडल के सभी जीजान से लगे हुए है कार्यकर्ताओ का हौसला बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर के सभी आये हुए अतिथि जिनको छःग की जिम्मेदारी मिली है।

पीएससी घोटाले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज एबीवीपी का विशाल आंदोलन

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् कल 6 अक्टूबर को पीएससी घोटाले के साथ-साथ प्रदेश की लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों की एक विशाल संख्या के साथ प्रदेश स्तरीय आन्दोलन करने जा रही है। इस छात्र आक्रोश रैली के निमित्त आज यहां परिषद के देवेन्द्र नगर स्थित प्रान्त कार्यालय में अभाविप के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव ने कहा कि सीजीपीएससी की 2021 परीक्षा में पीएससी चेयरमैन समेत कई अधिकारियों और नेताओं के बेहद करीबी रिश्तेदारों की भर्ती के बाद अब 2022 पीएससी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के उजागर होने

से पीएससी परीक्षा के लिए दिन-रात एक कर देने वाले युवाओं को न केवल निराशा और दुःख हुआ बल्कि वे आक्रोशित भी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गड़बड़ी की आशंका को प्रथमदृष्ट्या न नकारना भी गड़बड़ी के संदेह को ही पुष्ट करता है। इससे पीएससी की विश्वसनीयता को जो अपूरणीय क्षति हुई, वह तो शोचनीय है ही। ऊपर से प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना कि अबतक किसी परीक्षार्थी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, युवाओं को उद्वेलित करने के लिए पर्याप्त है। श्री वैष्णव ने आगे कहा कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर से आज चाकूबाजी, हत्या, लूट आदि आपराधिक मामलों के समाचारों की बाढ़ सी आ गई है। दिन ढलने के बाद लोगों को बाहर निकलने से पहले विचार करना पड़ रहा है। और एक तरफ प्रदेश सरकार है, जो अपराधियों को रोकने की बजाए उन्हें संरक्षण दे रही दे रही है, उन्हें बढ़ावा दे रही है। और तो और प्रदेश के गृहमंत्री ने आज तक इन अपराधों और अपराधियों के प्रति सख्त रूख दिखाना तो दूर, उनकी निन्दा तक नहीं की।

अचानक दिल्ली गए प्रदेश अध्यक्ष साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा में दूसरी सूची को लेकर हुए तनाव के बीच गुरुवार सुबह अचानक प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली रवाना हुए। खबर है कि छत्तीसगढ़ संगठन के कुछ और नेताओं को भी साव के साथ दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व अचानक चुनावी मामले पर एक बैठक करने जा रहा है।

अरुण साव के यूं अचानक दिल्ली रवाना होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि संगठन में पिछले दिनों टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की वजह से नाराजगी है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष साव को दिल्ली बुलाया गया।

केंद्रीय चुनाव समिति के राष्ट्रीय नेताओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे ओम माथुर, मनसुख मंडाविया भी साव के साथ गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं।

सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के संभावित नाम वायरल होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। गुजराती और सिंधी समाज के लोगों ने ओम माथुर को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। धरसींवा से अनुज शर्मा और साजा से ईश्वर साहू जैसे लोगों के नाम सामने आने के बाद स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

विरोध में अनुज शर्मा का पुतला भी जलाया गया। इसके बाद विरोध करने वाले लोग प्रदेश स्तर के नेताओं से मुलाकात करने पहुंच गए और उनका घेराव कर दिया। यह स्थिति भी संगठन में पसंद नहीं की जा रही हैं।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जब नाम तय किए जा रहे थे, तो केंद्रीय नेताओं को प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाई गई, उनका पूरा बायोडाटा दिखाया गया, उनकी छवि के बारे में जानकारी दी गई।

विधायक का मुखौटा पहनाकर भैंस पर बैठाया, विकास खोजने का सिलसिला जारी

रायपुर। रायपुर शहर में विकास खोजने के लिए प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बीजेपी ने पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक विकास उपाध्याय का मुखौटा पहनाकर एक शख्स को भैंस पर बैठा दिया। अनोखा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता यह कहते रहे कि, ऐ विकास कहां है तेरा विकास।

इससे 2 दिन पहले ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत बड़ी सी दूरबीन लेकर शहर की सड़कों पर विकास खोजने निकले थे। जिसके जवाब में विधायक विकास उपाध्याय ने भी अनोखा प्रदर्शन करते हुए कहा कि, बीजेपी नेताओं को दृष्टिदोष हुआ है। उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। इसके बाद फिर बीजेपी ने शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड नंबर- 38 में प्रदर्शन किया। वार्ड में जहां गड्ढे मौजूद थे वहां भैंस पर

विधायक का मुखौटा पहने शख्स बैठे शख्स से पूछा गया कि, आखिर शहर में जिस 36 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य का दावा कांग्रेस करती है वह कहां है।

भाजपा पार्षद दीपक जायसवाल ने कहा कि होर्डिंग और अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने शहर में 36 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। हम उन्हीं विकास कार्य को ढूंढने के लिए निकले हैं। लेकिन हमें शहर में कहीं भी विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है।

आज तालाब में सौंदर्यीकरण का काम नहीं हो रहा है। शहर में जहां भी निकलो चारों तरफ रोड और गलियों में गड्ढे ही नजर आएंगे। यही कारण है कि हम विधायक विकास उपाध्याय को भैंस में बैठाकर निकले हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि शहर में विकास कार्य कहां हुआ है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

तैयारी और जिज्ञासा से बनती है राहें आसानः आयुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर गरियाबंद ज़िले के राजिम स्थित पीजी कॉलेज के विद्यार्थी पहुँचे । राजनीति शास्त्र के इन 26 विद्यार्थियों ने एक ओर जहां राज्य निर्वाचन आयोग के सभी कक्षों का भ्रमण किया वहीं भ्रमण के अंत में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह , सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़ से सभाकक्ष में सौजन्य मुलाक़ात भी की । आयुक्त श्री ठाकुर ने सबसे पहले विद्यार्थियों के इस शैक्षिक भ्रमण को उनके ज्ञानवर्धन में सहयोगी बताया । उन्होंने राजधानी पहुँचे इन कोतुहूल बच्चों की निर्वाचन प्रक्रिया , आदर्श आचरण संहिता , निर्वाचन के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले ईवीएम, बैलट पेपर इत्यादि के बारे में जिज्ञासाओं को बारी बारी से शांत किया । उन्होंने विद्यार्थियों को हिदायत भी दी कि मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, उससे बारीकी से बातों को समझने में आसानी होती है । वहीं हर काम की बेहतरी के लिए तैयारी भी ज़रूरी है । यह तैयारी हममें आत्म विश्वास लाती है और मन के झिझक को भी दूर करती है। मुलाक़ात के दौरान पहले तो विद्यार्थी थोड़ा झिझक रहे थे लेकिन आयुक्त श्री सिंह के स्नेहिल व्यवहार से उत्साहित हो विद्यार्थियों ने अनेक सवाल किए । लगभग 45 मिनट की इस बातचीत के बाद विद्यार्थी बड़े संतुष्ट नज़र आये और आयुक्त और सचिव का धन्यवाद भी ज्ञापित किया । इस अवसर पर अवर सचिव द्व श्री आलोक श्रीवास्तव , श्री प्रणय वर्मा सहित आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहे ।

रायपुर महिला कांग्रेस बूथों में जाकर करेंगी भूपेश सरकार की योजनाओं का प्रचार

रायपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रभारी विजया एवं मालिनी द्वारा रायपुर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी व ब्लॉक अध्यक्षो की बैठक गांधी चौक स्थित कांग्रेस भवन में हुई। इस बैठक में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की जनहितैषी कार्यों और उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने महिलाओं के आर्थिक के लिए जो योजनाएं चला रही है उससे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उन्मूलक योजनाओं को जन जन तक बूथों के माध्यम से शहर महिला कांग्रेस को पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभारियों द्वारा निर्देशित किया गया। पूर्ववर्ती 15 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो जो बड़े बड़े कांड झलियारी कांड ,गर्भाशय कांड हुऐ जिनसे महिलाये पीड़ित हुई । उन बहनों का दर्द को समझते हुये हमारी कांग्रेस सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना,हाट बाजार क्लीनिक ,डॉ खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य योजना,मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना 25 लाख तक निशुल्क ईलाज के माध्यम से महिलाओ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की। गौधन न्याय योजना के माध्यम से महिलाओ को गौठान में आर्थिक लाभ व रोजगार मिल रहा। नये नये उत्पाद महिला बहनो के द्वारा गोबर से बनाकर विदेशों में निर्यात किया जा रहा ।बिजली बिल हाफ से भी घरों में बचत हो रही है। वही केंद्र सरकार सिलेंडर के भाव 400 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपए कर दिया जिससे आम जनता परेशान हैं।

मोदी-शाह की मनमानी के खिलाफ भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता टिकट वितरण प्रक्रिया में मोदी-शाह की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।ओम माथुर अरुण साव को कोस रहे है।भाजपा की घोषित 21 प्रत्याशियों के खिलाफ गुस्सा खत्म हुआ ही नही था कि अब प्रत्याशियों की वायरल सूची के बाद

भाजपा नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे, कालिख पोती जा रही है, पुतला जलाया जा रहा है। जब अधिकृत सूची आएगी तो भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता तांडव करेंगे, दावेदार एक-दूसरे का सिर नोचेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी अनुशासित दल और कैडर बेस पार्टी बताती थकते नही थी उसका पोल प्रदेश में खुल गया जब वायरल प्रत्याशियों की सूची के बाद टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ जूतों का माला लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के घर पहुँच रहे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि असल में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भाजपा में टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं दावेदारों की सुन ही नहीं रहा है। उसने पसंद, न पसंद पूछ नहीं रहा है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व मनमानी कर रहा है।

निगम सभापति दुबे ने किया एक करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। पं. भगवती चरण शुक्ल वार्ड में लगभग एक करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का बुधवार को नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने भूमि पूजन किया। विभिन्न स्थानों पर पेवर लगाने सहित विविध सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ रूपये की लागत से शीघ्र करवायें जायेंगे। वार्ड के छत्तीसगढ़ कॉलेज के समीप लगभग 98 लाख रूपये की लागत से गन्दे पानी की निकासी के सुगम प्रबंधन हेतु नए नाले का निर्माण अधोसंरचना मद से होगा। नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति जोन 4 पदेन अध्यक्ष, वार्ड 57 के पार्षद प्रमोद दुबे ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बाकर अब्बास सहित वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, गणमान्य जनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, नवयुवकों के साथ मिलकर श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर पण्डित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चौक- चौराहों एवं चबूतरों में आवश्यक सुधार एवं मरम्मत सहित उनके जीर्णोद्धार के कार्य 9 लाख 95 हजार रूपये, विभिन्न सामुदायिक भवनों की आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य 7 लाख 49 हजार रूपये, कुंदरापारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य 10 लाख 21 हजार रूपये, फरिश्ता अपार्टमेंट, पेंशनबाड़ा एवं कुंदरापारा में जीपीएस एवं विकास के कार्य 5 लाख 23 हजार रूपये, पेंशनबाड़ा एवं शैलेन्द्र नगर में नाली, पुलिया निर्माण 10 लाख रूपये, काली माता मन्दिर के समीप सौंदर्यीकरण का कार्य 1 लाख रूपये की भूमिपूजन की।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉ. प्रवीण वर्मा

रायपुर। डॉ. प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं संतकुमार नेताम को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। साल 2021 में सीजीपीएससी एग्जाम हुआ था। इसका रिजल्ट आने के बाद विवादों में घिरा रहा। बीजेपी सीजीपीएससी स्कैम को लेकर कांग्रेस सरकार को लगातार घेरती रही है। सरकार और सोनवानी में सांगागांठ के आरोप भी लगाती रही है। भाई भतीजावाद के भी आरोप लगाए हैं। सीजीपीएससी अध्यक्ष सोनवानी को हटाकर अब पीएससी में सदस्य पद पर रहे डॉ. प्रवीण वर्मा को सीजीपीएससी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 के खंड(1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विनियम, 2001 के विनियम 3(2) में निहित प्रावधानों के तहत डॉ. प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विनियम, 2001 के उप विनियम 3(1) में निहित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर संतकुमार नेताम को नियुक्त किया गया है।

धान खरीदी भूपेश सरकार अपने दम पर करती है, केंद्र का योगदान शून्य

रायपुर। अनुराग ठाकुर ने धान खरीदी पर एक बार फिर से झूठ बोला कि धान खरीदी केंद्र करती है जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के दम पर खरीदती है, धान खरीदने में केन्द्र सरकार का एक पैसे का भी योगदान नहीं है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है इसके लिये मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तथा इस ऋण के लिये बैक गारंटी राज्य सरकार देती है तथा धान खरीदी में जो घाटा होता है उसको भी राज्य सरकार वहन करती है पिछले वर्ष मार्कफेड ने लगभग 35000 करोड़ का ऋण धान खरीदी के लिये लिया था। मोदी सरकार तो घोषित समर्थन मूल्य

से 1 रूपये भी ज्यादा कीमत देने पर राज्य सरकार को धमकाती है की वह राज्य से केन्द्रीय योजनओं के लिये लगने वाला चावल नही खरीदेंगे। अकेली छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपने धान उत्पादक किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत देती है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले वर्ष धान की कीमत 2640 मिली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जैसे राज्यों में तो किसानों को धान का मूल्य 1100 रूपये मिलता है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां किसानों को प्रति एकड़ धान पर 9,000 रूपये तथा अन्य फसल पर 10,000 रूपये की इनपुट सब्सिडी मिलती है। कांग्रेस सरकार में चालू खरीफ सीजन में 20 क्विंटल धान की खरीदी 2800 रू. की दर पर की जायेगी।

अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास पर भी झूठ बोला मोदी सरकार के गरीब विरोधी नीति के कारण केन्द्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है। राज्य के प्रतीक्षारत 7 लाख आवासों की प्रतीक्षा सूची को केन्द्र लंबे समय से रोके रखा हैं, जिसके कारण राज्य आवासहीनों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को अनेकों बार पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने की मांग किया लेकिन राज्य के प्रति दुर्भावना के कारण भाजपा की केन्द्र सरकार ने राज्य के आवासों को लटकाये रखा है केन्द्र के इस दुर्भावना पूर्ण रवैये से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य अपनी आवास योजना शुरू किया है। जिसमें 7 लाख आवासहीनों को भूपेश सरकार स्वयं आवास उपलब्ध करायेगी। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आबंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है।

मिशन अमृत 2.0 की हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में कार्यो की प्रगति पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की आठवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत स्टेट वाटर एक्शन प्लान टैंच 2.0 पर चर्चा की गई। मिशन अमृत 2.0 के संबंध मे राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अमृत मिशन 2.0 के

अंतर्गत किये गये कार्यो की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के कोरबा, भिलाई, दुर्ग, अम्बिकापुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और जगदलपुर का सिटी वाटर एक्शन प्लान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया गया है, इसके आधार पर ही स्टेट वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जिसकी लागत करीब 911 करोड़ रूपये है।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव श्री एम.डी कावरे और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज तम्बोली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.